नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 3 अंक 2
मार्च, 2001 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे शासक गिरोह को ध्वस्त करो! चोरों लुटेरों, भ्रष्ट विलासियों के इस फर्जी लोकतंत्र को खारिज करो!

सम्पादक

जिस व्यवस्था में हर वर्ष सैकड़ों खरब की कानूनी लूट होती है, उसी में घपले और घोटाले भी होते हैं। पूंजीवाद से सदाचार की उम्मीद करना बेकार है, उसे तबाह कर देना ही एकमात्र समाधान है!

तहलका डाटकाम के भण्डाफोड़ ने नैतिकता, शुचिता, मर्यादा की बातें बघारने वालों की धोती खींचकर उन्हें नंगा कर दिया है। देश को रामराज्य में ले जाने वाली पार्टी के अध्यक्ष महोदय एक लाख रुपये की गड्डी हथियाते धरे गये तो फटा कुर्ता पहनने वाले घृणित नौटंकीबाज जार्ज फर्नाण्डीज की सखी जया जेटली ने दो लाख रुपये 'साहिब' के नाम पर ले लिये। रक्षा मंत्रालय के निचले अफसरों से लेकर प्रधानमंत्री के घर और दफ्तर में बैठे दलालों तक की भूमिकाओं वाली तहलका की यह वीडियो फिल्म बेशर्मी, बेहयाई और घिनौने भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी कहती है कि इसके आगे घटिया से घटिया ब्लू फिल्म भी 'सम्पूर्ण रामायण' जैसी लगने लगेगी।

रक्षा मंत्रालय के निचले अफसरों से लेकर प्रधानमंत्री के घर और दफ्तर में बैठे दलालों तक की भूमिकाओं वाली तहलका की यह वीडियो फिल्म बेशर्मी, बेहयाई और घिनौने भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी कहती है कि इसके आगे घटिया से घटिया ब्लू फिल्म भी 'सम्पूर्ण रामायण' जैसी लगने लगेगी।

तहलका के भण्डाफोड़ ने सिर्फ उस बात को साबित ही किया है जिसे आम जनता रोज देखती-सुनती और भुगतती रही है। यह पूरी व्यवस्था सर से पांव तक भ्रष्टाचार के बदबूदार दलदल में डूबी हुई है। अब तो कन्नौज के इत्र और पेरिस के सेन्ट से भी इसकी बदबू दबाने लायक नहीं रह गयी है। तहलका के वीडियो टेपों ने तो बस एक सड़कर बजबजाती हुई व्यवस्था के घिनौने शरीर के एक हिस्से से कपड़ा उठाया है।

यह गंदगी सामने आते ही दिल्ली में चलने वाले लोकतंत्र के फूहड़ स्वांग में वीभत्स, विद्रूप और हास्य रस से भरे नये-नये दृश्य दिखाई पड़ने लगे हैं। सरेआम नंगा हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत सत्तारूढ़ गठबंधन ने जिस बेहयाई का परिचय दिया है वह 75 साल से राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ठेकेदारी चला रहे संघियों और पाखंड के साक्षात अवतार समाजवादियों की खास विशेषता है। सारे के सारे चोर एक दूसरे को बचाने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में चीख-पुकार मचाने की कोशिश कर रहे हैं। फासिस्टों का पुराना मंत्र है -- एक झूठ को सौ बार बोलो तो वह सच हो जाता है। उन्हें उम्मीद है कि यह मंत्र फिर उनके लिए संकटमोचक सिद्ध होगा। आखिर मीडिया को जेब में करके मचाये शोर-शराबे में ही तो वह अपने काले कारनामों को छुपाते आये हैं। लेकिन इस बार शायद यह तरीका काम न आये।

सरकार पर संकट के बादल घहराते ही भाजपा के असली दोस्त-- तमाम पूंजीपति और उनकी संस्थाएं-- उसकी मदद के लिए आ खड़े हुए। फिक्की, एसोचैम, सी आई आई आदि ने इसमें अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश देखी तो राहुल बजाज, बी एम मुंजाल, नंदा और मोदी ने सरकार को करीब-करीब क्लीन चिट ही दे दी। आखिर क्यों न करें? इस सरकार से ज्यादा तत्परता से उनकी सेवा भला कौन करेगा? और अभी-अभी तो वित्तमंत्री ने बजट में उन पर तोहफों की बौछार की है। असलियत तो यह है कि यह बजट अपने आप में खुल्लम-खुल्ला डकैती, राहजनी, हत्या (मजदूरों को सड़कों पर धकेलकर) और सबसे निचले दर्जे के भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। लेकिन इस व्यवस्था में यह पूरी तरह कानूनी है।

दलाली, रिश्वतखोरी, सोनपुर मेले में बिकने वाले गाय-बैलों की तरह सांसदों-विधायकों की खरीद-फरोख्त से लेकर बाल्को और मॉर्डन फूँड जैसे उद्योगों को कौड़ियों के मोल बेचने और हथियारों की खरीद में खायी जाने वाली दलाली भारतीय राजनीति की एक स्थायी परिघटना बन चुकी है। इससे अलग कुछ हो भी नहीं सकता। दरअसल यह समूचा शासनतंत्र आज इस हालत में पहुंच चुका है कि दलालों

(पेज 9 पर जारी)

केन्द्रीय आम बजट 2001-2002

वजीरे खजाना! यह सौदा महंगा पड़ेगा

अरविन्द सिंह

पिछली सदी में तीस के दशक की महामंदी के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो कदम उठाये थे उन्हें 'न्यू डील' कहा गया था। इसी तर्ज पर भीषण मन्दी के भंवर में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए यशवन्त सिन्हा ने इस साल बजट में जो कदम उठाये हैं उसे 'न्यू डील' का नाम दिया है।

'न्यू डील' -- यानी नया सौदा। रूजवेल्ट ने अपने 'न्यू डील' के जरिये पूंजीपतियों को भरोसा दिलाया था कि अगर तुम लोग मुनाफे की लूट को आगे जारी रखना चाहते हो तो सरकार के कल्याणकारी पर्दे की ओट में छुप जाओ। लेकिन यशवन्त सिन्हा का 'न्यू डील' इससे उलट है। उन्होंने फैसलाकुन अन्दाज में भारतीय राज्य के कल्याणकारी लबादे को उतार फेंकने का ऐलान किया है और देशी-विदेशी पूंजीपतियों को छुट्टा छोड़ दिया है कि देश की मेहनतकश जनता पर टूट पड़ो।

मुनाफाखोरों को तिजोरियां भरने का मौका छप्पर फाड़ शैली में

देशी मुनाफाखोरों की तिजोरियां भरने के लिए इस बार उद्योगों पर लगने वाले टैक्सों में तरह-तरह की रियायतें देकर 'छप्पर फाड़' ढंग से तिजोरी भरने का मौका दिया गया है। तमाम घरेलू कम्पनियां अपने शेयरधारकों को जो लाभांश देती हैं, उस पर लगने वाला टैक्स 22.6 प्रतिशत से घटाकर सीधे 10.2 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर दो प्रतिशत गुजरात भूकम्प राहत अधिभार (सरचार्ज) इसमें जोड़ भी दिया जाये तो भी सीधे 10 प्रतिशत की छूट मिली है। एक पूंजीवादी अखबारी घराने के ही एक नामी गिरामी अंग्रेजी अखबार 'दी इकोनामिक टाइम्स' के हिसाब को अगर सही मानें तो सिर्फ इस कर राहत से पचास सबसे बड़ी घरेलू कम्पनियों को कुल 791.24 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके अलावा उद्योगों पर लगने वाले सीधे टैक्स, (जिसे कारपोरेट टैक्स कहा जाता है) के अधिभार पर भी छूट दी गयी है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस कर राहत से भी सबसे बड़ी पचास घरेलू कम्पनियों को लगभग 1136 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचेगा।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं -- जैसे सड़कों, रेलवे, सिंचाई व्यवस्था, बिजली, दूरसंचार आदि में पूंजीनिवेश करने वाले देशी-विदेशी पूंजीपतियों को आने वाले दस वर्षों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन निवेशों से मिलने वाले ब्याज, लाभांशों या लम्बे समय वाले लाभों पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह खाद्यान्नों के रखरखाव, भंडारण और इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट के निजी कारोबारियों को भी पांच वर्षों तक टैक्सों में पूरी छूट दी जायेगी और अगले पांच वर्षों तक 30 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस उपाय से इस क्षेत्र में पूंजी लगाने वालों के मालामाल होने का भरपूर मौका बजट ने दिया है।

यशवन्त सिन्हा का यह नया सौदा कोई हैरतनाक बात नहीं है। पिछले दस वर्षों से भारतीय राज्य इसी दिशा में बढ़ता आया है। नरसिंह राव-मनमोहन सिंह एण्ड कम्पनी ने शुरुआती प्रस्ताव पेश किया था जिसे संयुक्त मोर्चा सरकार ने आगे सरकाया और कीचड़ में कमलवत खिले वाजपेयी और उनके विपत्ति काल के सभी सहयोग एकजुट होकर यशवन्त सिन्हा के इस नये सौदे तक खींच लाये हैं (हर तरह की

(पेज 9 पर जारी)

भीतर के पन्नों पर

1. बिखराव के कारणों की ईमानदार पड़ताल जरूरी - 3
2. पार्टी की बुनियादी समझदारी - 4
3. स्वर्ग का तलघर अंधेरा - 5
4. क्रान्ति की सचित्र कथा - 6
5. मज़दूर वर्ग पर झपटते बहरी भेड़िये - 11
6. सरकार की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके दस वर्षों में 50 अरब रुपये हड़पे खाद कारखानों ने - 12

होंडा पावर प्रोडक्ट्स रुद्रपुर में ट्रेड यूनियन जनवाद की जीत

(बिगुल संवाददाता)

रुद्रपुर। होंडा पावर प्रोडक्ट्स कारखाने में कार्यरत श्रीराम होंडा श्रमिक संगठन के वार्षिक चुनावों में एक को छोड़कर सभी पदों पर मज़दूरों के उस पैनल को जीत हासिल हुई है, जिसने ट्रेड यूनियन जनवाद के उसूलों को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया था। पिछले 23 फरवरी को हुए चुनाव में एकजुट होकर एक पैनल से चुनाव लड़े विजयी पदाधिकारी हैं -- रामचन्द्र शर्मा (अध्यक्ष), किशन लाल (महामंत्री), अमर सिंह (कोषाध्यक्ष), ओ.पी. यादव (संगठन मंत्री), संतोष मणि त्रिपाठी (मंत्री प्रथम) और विजय कुमार आर्या (मंत्री द्वितीय)। पैनल से उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े महेश चन्द्र जोशी ही हारे हैं, लेकिन बाद में इन्हें भी कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुन लिया गया।

होंडा श्रमिक संगठन के चुनावों के नतीजे इस बात के सबूत हैं कि अगर आम मज़दूरों के बीच धीरज और सूझबूझ के साथ लगातार राजनीतिक प्रचार की कार्रवाई चलायी जाये तो उनकी चेतना को झकझोरकर जगाया जा सकता है। घटिया अर्थवादी यूनियनबाजी और जातिवाद- क्षेत्रवाद-गुटबाजी की पूंजीवादी तिकड़मों से बाहर निकलकर आम मज़दूर राजनीतिक उसूलों और मज़दूर वर्ग के आम हितों के मुद्दों पर अपनी वर्गीय एकजुटता कायम कर सकते हैं, यह कोई अनहोनी बात या ख्याली उड़ान नहीं है।

इस चुनाव में खड़े हुए पैनल

(पेज 2 पर जारी)

बजा बिगुल मेहनकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन चुनाव में मज़दूरों द्वारा बांटा गया पर्चा

संगठन को मजबूत और जनवादी बनाओ

साथियो,

एक कठिन चुनौतीपूर्ण समय में 'श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन' का वार्षिक चुनाव होने जा रहा है। एक ऐसे समय में जबकि हमारे कारखाने में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और तरह-तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म है। हमारे दो साथी कारखाने से निष्कासित है और प्रबन्ध तंत्र लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे संगठन का जुझारूपन लगातार खत्म होता जा रहा है और संगठन की ताकत कमजोर दिखने लगी है। यह स्थिति उस वक्त है जबकि कारखाने से लेकर पूरे देश के पैमाने पर हालात मज़दूरों के विपरीत है।

सोचो दोस्तो, जिस संगठन ने अपने एकताबद्ध और जुझारू संघर्षों से हमें तमाम हक और सहूलियतें दिलायी हो, क्षेत्र के तमाम मज़दूर संघर्षों में भी हिस्सेदारी करके अपनी वर्गीय एकता प्रदर्शित की हो और जिसे पूरे इलाके की आम जनता संघर्षशील और सम्मानपूर्ण नजर से देखती रही हो, उस संगठन में अचानक गिरावट की स्थिति क्यों आ गयी? क्या, निजी स्वार्थ की राजनीति ने अस्तित्व का संकट पैदा नहीं कर दिया है? क्या गुटबाजी व जातिवाद-क्षेत्रवाद की बाड़ेबन्दी एक घृणित राजनीति नहीं है? आखिर, नियमित व दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के बंटवारे की ज़मीन कहां से पैदा हुई है? क्या इसका एक प्रमुख कारण संगठन के गैरजनवादी हो चुके चरित्र में नहीं निहित है?

हमारी यह स्पष्ट मान्यता है कि जो संगठन जनवादी तौर-तरीके से चलते हैं और जिसमें पारदर्शिता होती है, वह ट्रेड यूनियन संगठन ठोस और मज़दूरों के हितों की रक्षा करने की स्थिति में रहता है। लेकिन, वर्तमान में हमारा संगठन 'जिसकी ढपली उसका राग' के तर्ज पर चल रहा है। इस अफसोसजनक स्थिति पर हमें विचार करना होगा और इसे बदलने की पहल लेनी ही होगी।

पहली बात तो यह है कि संगठन के चुनाव की प्रक्रिया ही गैर जनवादी है – पहले पदाधिकारियों का चयन फिर इन पदाधिकारियों द्वारा अपनी कार्यकारिणी का गठन। जबकि सही व जनवादी तरीका ठीक इसके विपरीत होता है – यानी यूनियन सदस्यों द्वारा सीधे कार्यकारिणी का चुनाव हो और फिर नयी कार्यकारिणी अपने पदाधिकारियों का चुनाव करें। यही तरीका हमारे संगठन के संविधान में भी उल्लिखित है। यूनियन सदस्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि चुनावों में वे किसी भी उम्मीदवार को नामजद कर सकें और वापस बुला सकें। चुनाव में प्रत्याशियों को अपनी बात करने का पूरा मौका भी मिलना चाहिए।

दूसरा, कोई भी निर्णय पूरी कार्यकारिणी में लिया जाना चाहिए न कि कुछ एक प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा। संगठन की वर्तमान स्थिति में निर्णय लेने का काम सिर्फ अध्यक्ष/मंत्री करते हैं और कार्यकारिणी महज कुछ खानापूर्ति के लिए होती है। होना तो यह चाहिए कि तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सदस्यों की आम सभाओं में विस्तार से विचार हो, साधारण कार्यकर्ताओं के परामर्श व सुझावों पर गम्भीरता से गौर किया जाये और कार्यकारिणी अपने कामों से समय-बा-समय सदस्यों को अवगत कराती रहे। कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाये और अल्पमत के मत को भी महत्व देते हुए विचारार्थ रखा जाये। पारदर्शिता के लिए आय-व्यय की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए।

हमारा दृढ़ मत है कि इन्हीं प्रश्नों के मद्देनजर ही हम अपने संगठन को जुझारू और परिपक्व बना सकते हैं। यहीं हम यह भी कहना चाहते हैं कि संगठन के कामों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नेतृत्वकारी निकाय में मज़दूर हितों के लिये जागरूक और एक गुंथी हुई टीम होनी चाहिए। ऐसी एक टीम ही वक्त-बेवक्त महत्वपूर्ण व सूझ-बूझ भरे फैसले ले सकती है।

हमने, संगठन की वर्तमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस चुनाव में एक टीम के रूप में भागीदारी करने का निर्णय लिया है। यह मानते हुए भी कि चुनाव की वर्तमान पद्धति गैर जनवादी है। इसे बदलने के लिये हम कृत संकल्प हैं। हमने यूनियन के जनवादी चरित्र को बहाल करने और इसे एक संघर्षशील और मजबूत यूनियन के रूप में ढालने का संकल्प बांधा है। इस दिशा में हमने तो महज पहल ली है, सबके साझा प्रयास से ही इस कठिन मुकाम को पार किया जा सकता है, और हमें इस मुकाम को पार करना ही होगा।।

हम सभी ईमानदार और संगठन के अस्तित्व की रक्षा के लिये चिन्तित साथियों का आह्वान करते हैं कि हमारी पहलकदमी को आगे बढ़ायें और अपने अमूल्य मत का सही और सटीक इस्तेमाल करें।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित,

रामचन्द्र शर्मा, महेश चन्द्र जोशी, किशन लाल, अमर सिंह, विजय कुमार आर्या, ओ.पी. यादव, संतोष मणि त्रिपाठी

आपस की बात

क्रांति के सपने को भारत की जमीन पर उतारेंगे

बिगुल मिला। बिगुल से जुड़े सभी क्रान्तिकारी साथी हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। आप द्वारा प्रकाशित साहित्य व पत्रों द्वारा आपके साथ एक आत्मीय रिश्ता क़ायम हो गया है। सभी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के भीतर कम्युनिस्ट भावना व नैतिकता का गुण और व्यापक लक्ष्यों की एकता उनकी एकता को इसी तरह से मजबूत बनाती है। हम सभी क्रान्तिकारी जनता के साथ जुड़कर क्रान्ति के सपने को भारत की जमीन पर उतारेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपसे अनुरोध है कि हमारे पते पर नियमित पत्रिका भेजते रहें।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित,

विनय कुमार
पलामू, झारखंड

मैं बिगुल का नियमित पाठक हूं। मैंने सितम्बर माह में एक वर्ष के लिए सहयोग राशि भेजी थी। अक्टूबर प्रथम अंक-9 के बाद मुझे बिगुल नहीं मिला है। कृपया शीघ्रताशीघ्र मुझे बिगुल भेजने का कष्ट करें।

आर.एन.मल्ल,
देहरादून

बिगुल लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां शुगर मिल गेट के सामने इफ्टू का कार्यालय में एक छोटी सी लाइब्रेरी तथा वाचनालय भी है। यहां क्रान्तिकारी साहित्य के काफी पाठक हैं। कुछ छोटे-मोटे संघर्ष भी चलते रहते हैं। बिगुल नियमित भेजते रहें। साथ ही अन्य क्रान्तिकारी साहित्य भी भेज सकें तो आभार होगा। बिगुल के सभी साथियों को सलाम!

महेश महर्षि,
श्री गंगा नगर

कविता

उठो! देश के ओ मज़दूरो आगे बढ़ना है,
हमें अब राज बदलना है, हमें अब आगे बढ़ना है।
रीतियां अन्धी छोड़ो नींद गफलत की त्यागो
ओह कभी न झुकना है हमें अब...
उठो! देश के ओ मज़दूरों आगे बढ़ना है हमें अब...
भगतसिंह की क्रान्ति को हमें अब आगे लाना है
हमें अब राज बदलना है, हमें अब
देशी-विदेशी लुटेरों के खिलाफ, हमें अब एक हो जाना है।
हमें अब राज बदलना है, हमें अब आगे बढ़ना है।

–जयकरण (मज़दूर)
ए.एस.पी.लि., गज़रौला।

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं में, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मजदूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों का नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मजदूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनवाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

ट्रेड यूनियन जनवाद की जीत

(पेज 1 से आगे)

ने आम मज़दूरों से वोट बटोरने के लिए कोई चारा नहीं फेंका। कोई हवाई तीर-तुमार नहीं बांधा। वे जनवाद के उसूलों को यूनियन में लागू करने को प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े और सिर्फ यह आश्वासन दिया कि आम मज़दूरों की भागीदारी से यूनियन का जनवादी चरित्र बहाल करने और उसे एक संघर्षशील मजबूत यूनियन के रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। अब तक चली आ रही ट्रेड यूनियन नौकरशाही से ऊबे आम मज़दूरों ने पैनल के आह्वान को गम्भीरता से लिया और उन्हें जिताकर जनवाद के उसूल के प्रति अपनी एकजुट भावना का इजहार दिया।

हालांकि इस पैनल को हराने के लिए मालिकान ने तरह-तरह की तिकड़में चलीं। जात-पांत, पूरब-पश्चिम, पहाड़-मैदान आदि के बंटवारे पैदा कर मज़दूरों की एकता को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी। लेकिन पैनल के घनीभूत प्रचार एवं जनसम्पर्क से मज़दूरों में वर्गीय भावना कमजोर नहीं की जा सकी और आम मज़दूरों ने हर चाल को नाकाम कर अपनी यूनियन को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट दिया।

इस चुनाव के पहले यूनियन के चुनावों में अब तक यह चलन था कि पदाधिकारी सीधे चुने जाते थे और ये चुने हुए पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यों को मनोनीत करते थे। यह जनवाद के उसूलों का खुला उल्लंघन था। पदाधिकारी चहेते लोगों की कार्यकारिणी बनाकर मज़दूरों पर थोप देते थे और फिर साल भर अपनी मनमानी करते थे। लेकिन, इस बार यह चलन तोड़ दिया गया। इस बार कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव भी अलग-अलग शॉपों-यूनिटों से सीधे आम मज़दूरों ने किया।

होंडा श्रमिक संगठन में जनवाद की जीत मज़दूरों के संघर्ष के लिए काफी अहमियत रखती है। मज़दूरों को इस बड़ी उपलब्धि की हिफाजत करनी होगी और इसकी बुनियाद पर मज़दूर आन्दोलन का क्रान्तिकारीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ते जाना होगा, क्योंकि अभी काफी लम्बा रास्ता तय करना है।

बिगुल पोस्टर श्रृंखला के तहत प्राप्त करें दो आकर्षक पोस्टर

कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर

बिगुल पोस्टर -1

महान पेरिस कम्यून की 128वीं जयन्ती (18 मार्च) के अवसर पर

बिगुल पोस्टर -2

प्राप्ति स्थान

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020
फोन : 788932

बिगुल यहां से प्राप्त करें

◆ शहीद पुस्तकालय, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर, मऊ** ◆ मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज), मऊनाथभंजन, मऊ ◆ जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर** ◆ विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, **गोरखपुर** ◆ विश्वनाथ मिश्र, नेशनल पी.जी. कालेज, **बड़हलगंज**, गोरखपुर ◆ ओमप्रकाश, 69, बाबा का पुरवा (पुराना), पेपर मिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ◆ जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, लखनऊ, (शाम 5 से8·30) ◆ राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ◆ विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, **लखनऊ** ◆ विजय कुमार, 55/3, ई.डब्ल्यू.एस., आवास विकास, **रुद्रपुर** (ऊधमसिंहनगर) ◆ रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, **रुद्रपुर** (ऊधमसिंहनगर) ◆ रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, पन्तनगर ◆ कृष्णगोविन्द सिंह, बी-18, बिड़ला छात्रावास, बी.एच.यू. **वाराणसी** ◆ प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, बी.एच.यू. **वाराणसी** ◆ राजीव वर्मा द्वारा डा. जे.पी. वर्मा, बी.पी. 82, पटेलनगर, **मुगलसराय**, वाराणसी ◆ राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, **रेणुकूट**, सोनभद्र ◆ सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार-एक, **नई दिल्ली** ◆ ललित सती, एल.आई.सी., **फैज रोड शाखा, दिल्ली** ◆ नई किरण पुस्तक भंडार, एफ-56, हरकेश नगर, ओखला, नई दिल्ली, ◆ पंकज कुमार, 256, मॉडल टाउन, सोनीपत, हरियाणा ◆ डी. के. सचान, कृषि विज्ञान केंद्र, विकास भवन, नई कलक्ट्रेट, **गाजियाबाद** ◆ सुनील कुमार सिंह, सेक्टर-12 बी, 3159, बोकारो इस्पातनगर, **बोकारो** ◆ गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो. तेघड़ा, **बेगूसराय** ◆ पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, **पटना** ◆ समकालीन प्रकाशन (प्रा.) लि. पुस्तक बिक्री केन्द्र, आजाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** ◆ विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक ,जबलपुर ◆ नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुन्दल, ग्रा/पो **सन्तनगर**, जिला-सिरसा ◆ राकेश गोरखा, सरस्वती पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी, **दार्जीलिंग** ◆ बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, **कलकत्ता** ◆ शर्मा बुक स्टाल, थाना रोड, चराली, तिनसुकिया नेपाल ◆ विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्रवनपथ, बुटवल, रुपनदेई, नेपाल ◆ विशाल पुस्तक सदन, बिजुवार बाजार, प्यूठान राप्ती अंचल ◆ विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन, बुटवल, लुम्बिनी, नेपाल

बिखराव के कारणों की ईमानदार पड़ताल ज़रूरी

साथी सियाशरण की चिन्ताओं से असहमत नहीं हुआ जा सकता। सचमुच यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंकलाबी ताकतों के बिखराव के कारण देश की मेहनतकश जनता पर पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के लगातार बढ़ रहे हमलों के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक आन्दोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। साथी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी ही है जिसे स्वीकार न करना वस्तुगत सच्चाई से आंखें चुराना होगा। एक सर्वभारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण और गठन के बिना क्रान्ति तो क्या किसी देशव्यापी राजनीतिक आन्दोलन की कल्पना भी सम्भन नहीं। इस सच्चाई से भी कोई क्रान्तिकारी ग्रुप शायद ही इनकार करे। इसके बावजूद बिखराव और टूट-फूट का सिलसिला रुक नहीं रहा है, गतिरोध टूट नहीं रहा है।

इस वस्तुगत सच्चाई का विश्लेषण आखिर कैसे किया जाये? हल्के-फुल्के ढंग से इस पर कोई राय बनाने के बजाय हमें इसका गहराई से विश्लेषण करना होगा। न थोथे आशावाद या आत्मतुष्टि से काम चलने वाला है और न ही निराशा और अवसाद के गर्त में जाने से। परस्पर दोषारोपण या आत्मभर्त्सना से भी यथास्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए, मेरी समझ से सबसे अहम बात तो यह है कि समस्या के विश्लेषण के लिए सही मार्क्सवादी पहुंच और पद्धति का प्रयोग किया जाये ओर समस्या को समग्रता में समझा जाये। मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार वस्तुगत और मनोगत कारणों की सही पड़ताल हमारे आन्दोलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाये। ऐसा नहीं करने पर वह रास्ता नहीं दिखेगा, जिसपर चलकर एक जुझारू क्रान्तिकारी पार्टी का निर्माण व गठन हो सके।

साथी सियाशरण शर्मा ने यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि भारतीय क्रान्ति की मंजिल के सवाल पर एक अवस्थिति (पोजीशन) पर खड़े क्रान्तिकारी ग्रुपों के बीच भी एकता क्यों नहीं हो पा रही है? नव जनवादी क्रान्ति मानने वाले ग्रुप भी क्यों अलग-अलग हैं और समाजवादी क्रान्ति मानने वाले भी टूट-फूट बिखराव के शिकार क्यों हैं? साथ ही उन्होंने इस चिन्ता का भी दो टूक इजहार किया है कि विभिन्न विचारधारात्मक राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आखिर यह स्थिति भी क्यों नहीं बन पा रही है कि कम से कम कुछ साझा मुद्दों पर ही सही कोई साझा मंच बने। लेकिन साथी इस दुखद स्थिति का कारण सिर्फ संगठन के मामले में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी खेमे में व्याप्त अराजकता और वैचारिक श्रेष्ठता का अहंकार है, यह कहना बहुत अधिक सरलीकरण होगा।

साथी सियाशरण, हमें इस बात का उत्तर ढूंढना होगा कि संगठन के मामले में यह अराजकता क्यों है और अगर कहीं किसी किस्म का अहंकार एक नकारात्मक भूमिका निभा-रहा है तो यह कहां से पैदा हो रहा है और इस प्रवृत्ति को रोकने का क्या कोई कारगर उपाय नहीं है?

मेरी समझ से क्रान्तिकारी वामपन्थी खेमे में फैली टूट-फूट, बिखराव, तरह-तरह की संकीर्णताओं और तमाम किस्म की गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्तियों-व्यवहारों की मौजूदगी का एक प्रमुख बुनियादी कारण यह है कि अधिकांश ग्रुपों-संगठनों ने चारु मजूमदार की मध्यवर्गीय अतिवामपंथी अराजकतावादी नौकरशाहाना-फरमानशाहाना सांगठनिक लाइन से निर्णायक विच्छेद नहीं किया है और वे क्रान्तिकारी जनदिशा को नहीं लागू कर रहे हैं। जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट संगठन का प्राण होती है, लेकिन यही चीज़ ज्यादातर संगठनों में अनुपस्थित है। पार्टी-संगठनों को सर्वहारा वर्ग का अगुआ फौजी दस्ता बनाने के नाम पर नौकरशाही, फरमानशाही का बोलबाला है। नतीजा यह हुआ है कि संगठनों में स्वस्थ बहस-मुबाहसे नहीं चल पाते। स्वस्थ आलोचना-आत्मालोचना की संस्कृति मौजूद नहीं है। केन्द्रीयता संगठन के भीतरी जनवाद की जमीन पर खड़ी न होकर, संगठन की विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन, कार्यपद्धति-कार्यशैली और सही कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्कृति की एकता की बुनियाद पर नहीं वरन ऊपर से थोपी हुई है। संगठनों के भीतर जनवाद के नाम पर जो चीज़ मौजूद है वह है अतिजनवाद या औपचारिक जनवाद जो नौकरशाही केन्द्रीयता का ही दूसरा पहलू है।

बुनियादी तौर पर एक ही विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर खड़े संगठनों-ग्रुपों के बीच टूट-फूट का एक प्रमुख बुनियादी कारण यही है। जनवादी केन्द्रीयता के उसूलों पर औपचारिक प्रतिबद्धता प्रकट करने के बावजूद अमल में लागू न होने के कारण अधिकांश संगठनों में दो लाइनों का संघर्ष स्वस्थ ढंग से चल नहीं पाता। हम सभी जानते हैं कि दो लाइनों का संघर्ष किसी सच्चे कम्युनिस्ट संगठन की सप्राण आवयविक व्यवस्था (Living organic system) होता है। चूंकि, ठीक यही चीज़ मौजूद नहीं है, इसलिए तमाम गैर बुनियादी, गैर उसूली, परिधिगत, व्यावहारिक, रणकौशलात्मक (Tactical) मसलों पर संगठनों के भीतर उठने वाले मतभेद हल नहीं हो पाते और फूट-दर-फूट का अन्तहीन सिलसिला जारी है।

जब तक वर्ग समाज में सर्वहारा वर्ग की पार्टी की मौजूदगी है, तब तक यह होगा ही कि 'स्व' या अहंकार, कैरियरवाद, संकीर्णतावाद, आत्मधर्माभिमानता (Self-rightiousness) जैसी निम्न बुर्जुआ प्रवृत्तियां और विजातीय लाइनें या रुझानें लगातार सिर उठाती रहेंगी। इन प्रवृत्तियों-रुझानों-लाइनों के खिलाफ कम्युनिस्ट संगठनों के भीतर स्वस्थ ढंग से सतत संघर्ष चलाने और पार्टी संगठन का सतत क्रान्तिकारीकरण करते जाने की बुनियादी शर्त है कि सही अर्थों में जनवादी केन्द्रीयता लागू हो।

जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट संगठन के लिए सिर्फ एक ढांचागत या संरचनागत (Structural) सवाल नहीं है। यह बुनियादी तौर पर संगठन के रोजमर्रे के व्यवहार से लेकर जनता के बीच पार्टी कार्य के प्रति पहुंच का सवाल है। इसका रिश्ता इस सच्चाई से है कि इतिहास का निर्माण जनता करती है। यह संगठन के विभिन्न कमेटियों के बीच, नेतृत्व और कतारों के बीच, दो साथियों के बीच और समग्रता में संगठन और जनता के बीच जीवन्त रिश्तों से जुड़ा सवाल है। जनवादी केन्द्रीयता का सवाल मैं इसी रूप में उठा रहा हूं – एक सप्राण आवयविक व्यवस्था के रूप में, न कि रुढ़ ढांचागत अर्थ में। इसकी गैरमौजूदगी ही वह बुनियादी कारण है जिससे अधिकतर संगठन क्रान्तिकारी जनदिशा को भी व्यवहार में सही ढंग से नहीं लागू कर पा रहे हैं।जनवादी केन्द्रीयता और क्रान्तिकारी जनदिशा के बीच एक द्वंद्वात्मक सम्बन्ध है। संगठन जनवादी केन्द्रीयता पर अमल नहीं करेगा तो क्रान्तिकारी जनदिशा भी नहीं लागू होगी और क्रान्तिकारी जनदिशा न लागू होने से जनता के साथ सही अर्थों में जीवन्त रिश्ता नहीं बन सकेगा और संगठन के भीतर उभरने वाली विजातीय प्रवृत्तियों-रुझानों-लाइनों के खिलाफ सतत संघर्ष करते हुए उसके सतत क्रान्तिकारीकरण का काम नहीं हो सकेगा। नतीजा होगा ठहराव, संकीर्णतावाद, आत्मतुष्टि और आत्मश्लाघा में जीने की प्रवृत्तियों का गहरे तक जड़ जमाते जाना। आज, देश के बहुतेरे कमयुनिस्ट क्रान्तिकारी संगठन इसी दुर्भाग्यपूर्ण मुकाम पर खड़े हैं जिसकी ओर साथी सियाशरण ने इशारा किया है।

दो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठनों के बीच स्वस्थ संवाद, वाद-विवाद न होने का भी प्रमुख बुनियादी कारण जनवादी केन्द्रीयता की ग़ैर मौजूदगी ही है। यदि संगठनों के भीतर ही स्वस्थ बहस-मुबाहसे नहीं हो पाते, खुद अपने व्यावहारिक क्रियाकलापों की सही ढंग से समीक्षा-समाहार करने की एक ईमानदार

(शेष पेज 11 पर जारी)

भारत में वामपंथी क्रान्तिकारी आन्दोलन की समस्याएं – एक बहस

बिगुल में जारी इस बहस के अन्तर्गत **नवम्बर-दिसम्बर 2000 अंक** में साथी **सियाशरण शर्मा** (जमशेदपुर, झारखण्ड) की टिप्पणी **एकताबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण की समस्याएं** शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने कई विचारणीय मुद्दे उठाये थे।। बहस को आगे बढ़ाते हुए इस अंक में हम साथी **ललित** (दिल्ली) की टिप्पणी छाप रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि यह बहस और आगे बढ़ेगी और आन्दोलन की समस्याओं के बारे में देश भर में क्रान्तिकारी कतारों, हमदर्दों-शुभचिंतकों एवं वर्ग सचेत मज़दूरों की विभिन्न सोचों को जानने-समझने में मदद मिलेगी। इसलिए, पाठक साथियों से अपील है कि वे इस बहस में शिरकत करें और और अपनी चिन्ताओं-सरोकारों को 'बिगुल' के जरिये साझा करकें।

'बिगुल' के **फरवरी 1999** अंक में छपी साथी **पी.आर. हरणे** की चिट्ठी से शुरू हुई बहस में साथी सियाशरण की टिप्पणी से पहले अब तक बहस में जो टिप्पणियां छपी हैं, उनका सिलसिला इस प्रकार है – **अप्रैल 1999** अंक में साथी **संजय कुमार** *(वामपन्थी शिविर में बिखराव के बुनियादीकरण)*; **मई 1999** अंक में साथी **जी.पी. भट्ट** *(कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन में बिखराव का मूल कारण सही विचार-धारात्मक समझ का अभाव)*; साथी **अनादिचरण** की लम्बी **असमाप्त टिप्पणी की तीन किस्तें** क्रमश: **अगस्त 1999, नवम्बर-दिसम्बर 1999** और **जनवरी-फरवरी 2000** (शीर्षक क्रमश: *सवाल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, भारतीय क्रान्ति के कार्यक्रम पर नये सिर से बहस शुरू होनी चाहिए और संशोधनवादी और अन्य कुछ मध्यवर्गीय वामपंथी पार्टियों की कार्यक्रम सम्बन्धी सोच)*; **मई 2000** अंक में पुन: साथी **पी.आर. हरणे** की टिप्पणी *(बदली हुई विश्व परिस्थिति में क्रान्ति के स्तर निर्णय का प्रश्न)*; **जून-जुलाई 2000** अंक में गांव के ग़रीबों के बीच कार्यरत कुछ साथियों की टिप्पणी *(एकता के सवाल पर सही रुख अपनाने की ज़रूरत)*; **अगस्त 2000** अंक में साथी **सुखविन्दर** की टिप्पणी *(कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की एकता के लिए विचारधारात्मक संघर्ष ज़रूरी* और **सितम्बर 2000** अंक में एक अनाम बिगुल पाठक की टिप्पणी *(अन्तरविरोधों को नज़रअन्दाज करने से एकता नहीं कायम होगी)*।

साथी **अनादिचरण** के लेख की बाकी किस्तें भी हम अगले अंकों में प्रकाशित करेंगे जिससे बहस और आगे बढ़े। लेकिन बहस अधिक सार्थक और उपयोगी तभी बन सकेगी जब हमें आन्दोलन की विभिन्न प्रमुख धाराओं की ओर से कुछ प्रतिनिधि टिप्पणियां प्राप्त होंगी। हमें उम्मीद है कि आगामी अंकों में यह और अधिक गहराई और व्यापकता ग्रहण करेगी।

– सम्पादक

भविष्य निधि पर सरकारी डाका

(बिगुल संवाददाता)

उदारीकरण का सरपट दौड़ रहा घोड़ा मज़दूरों-कर्मचारियों को बुरी तरह रौंदने लगा है। निजीकरण- छंटनी-तालाबन्दी के तेज रफ्तार से जारी इस दौर में एक के बाद एक ख़तरनाक नीतियां कहर बरपा कर रही हैं। इसी क्रम में सरकार का एक और प्रस्ताव आया है। अब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले यदि अपने भविष्यनिधि से पैसा निकालता है तो उसे निकाली गयी राशि पर आयकर की मौजूदा सबसे ऊंची दर पर टैक्स चुकाना होगा।

पहले भविष्य निधि पर ब्याज घटाया गया, फिर इसका प्रबंधन निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव आया और अब इसके निकासी पर 30 फीसदी आयकर का प्रस्ताव आ गया। इस टैक्स से फिलहाल उन लोगों को छूट मिल गयी है, जिसकी कुल आय आयकर छूट सीमा के भीतर हो। इस नये टैक्स के पक्ष में तर्क यह दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की सच्ची ज़रूरत सेवानिवृत्ति के बाद ही पड़ती है और उससे पहले पैसा निकलवाने की प्रवृत्ति हतोत्साहित करने योग्य है।

क्या खूब तर्क है! यह बहुत सामान्य सी बात है कि कोई मज़दूर या कर्मचारी किसी आपातकालीन स्थिति में ही अपने भविष्य निधि से धनराशि निकालता है – मकान खरीदना या बनवाना हो, बीमारी की स्थिति हो अथवा शादी-विवाह जैसी स्थिति हो। ऐसी स्थिति में भी 30 फीसदी का भारी टैक्स, क्या अंधे के हाथ से लाठी छीनने जैसी बात नहीं है? सरकारी मंसूबे तो और भी ख़तरनाक है। वह पी.पी.एफ. जैसी योजनाओं पर टैक्स राहत भी खत्म करने वाली है।

दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि कोष में 45 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि है और सरकार अपने ज्यादातर खर्च इसी कोष के बूते चलाती है। ऐसा लगता है कि सरकार अपने भारी-भरकम राजस्व खर्चे के लिये और अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिये कर्मचारियों के जायज खर्चों पर रोक लगाकर भविष्य निधि पर डाका डालना चाहती है।

बेरोक-टोक (मुक्त) व्यापार: धन-दौलत का इंजन या लूट का इंजन

- पूंजीवाद के जन्म लेने के समय से ही व्यापार बढ़ता गया है पर इसके साथ ही दुनिया में अमीरी-गरीबी के बीच की खाई भी चौड़ी होती गई है। जहां गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों के लोगों का जीवन-स्तर सन 1800 में केवल तीन गुना ही बेहतर था वह 1900 में ऊपर उठकर 6 गुना बेहतर हो गया और सन 2000 में तो यह 20 गुना बेहतर हो गया है।
- पूरी दुनिया के आधे से भी अधिक लोगों (57%) के हिस्से में विश्व की कुल आमदनी का मात्र 6% ही आता है यानी ये लोग रोज 2 डालर से भी कम पर गुजर-बसर करते हैं।
- 1980 से 1996 के दौरान विश्व व्यापार में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई लेकिन 59 गरीब देशों की प्रति व्यक्ति आमदनी में वास्तविक गिरावट आई।
- साम्राज्यवादी देशों के भीतर भी आर्थिक विषमता बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर पांच में स चार पुरुष कर्मचारी 1995 में (1973 की तुलना में) वास्तविक रूप में 11% कम आमदनी पाए। काम करने वाले सबसे गरीब एक तिहाई लोगों की आमदनी में यह गिरावट 25% थी। इसी दौरान प्रति व्यक्ति देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में एक तिहाई की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई और अत्यन्त धनी 1% लोगों की सम्पदा दो गुनी हो गई। राष्ट्रीय सम्पदा के अंश के रूप में दुनिया भर में मज़दूरी घटी है जबकि बैंकों को दिये जाने वाले ब्याज और कारपोरेट मुनाफों में खूब इजाफा हुआ है।

('फ्री ट्रेड – इंजिन ऑफ ग्रोथ आर प्लण्डर', 'ए वर्ल्ड टु विन', नं.-26, 2000. के एक अंश का अनुवाद: **प्यारेलाल**)

विशेष सामग्री

पार्टी की बुनियादी समझदारी

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रांति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इस फौलादी सांचे में वोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये. हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसी उद्देश्य से, फरवरी, 2001 अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू किया है। इस अंक में दूसरी किश्त दी जा रही है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गयी श्रृंखला की एक कड़ी थी. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गयी थी। मार्च, 1974 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4,74,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नार्मन बेथ्यून इंस्टीच्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है- सम्पादक

(दूसरी किश्त)

माओ त्से-तुड. के उद्धरण

"हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने में नेतृत्व देने वाली शक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है।"

"हमारे विचारों को मार्गदर्शनकरने वाला सैद्धान्तिक आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद है।"

"क्रांति को विजय की मंजिल तक पहुंचाने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के सही होने पर और अपने संगठन की मजबूती पर निर्भर होना चाहिए।"

"मार्क्सवाद पर अमल करो और संशोधानवाद पर मत करो, एकताबद्ध हो जाओ, और फूट मत करो, निश्छल और निष्कपट बनो, साजिश और सांठगांठ मत करो।"

अध्याय-2

पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा

पार्टी के संविधान में विशेष रूप से यह उल्लिखित है: "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद- लेनिनवाद- माओत्से-तुड. विचारधारा को अपने चिन्तन का मार्गदर्शन करने वाला सैद्धान्तिक आधार मानती है।" इस मार्गदर्शक विचारधारा का अनुसरण करने में दृढ़ होना पार्टी-निर्माण के लिए अनिवार्य है। यह क्रान्तिकारी उद्देश्य के लिए विजय की गारण्टी है, और इसकी हिफाजत के लिए पार्टी के सभी सदस्यो को संघर्ष करना चाहिए।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुड. विचारधारा सर्वाधिक सही, सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक क्रान्तिकारी सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है।

मार्क्सवाद वह विज्ञान है जो प्रकृति के और समाज के विकास के नियमों की व्याख्या करता है। यह वह विज्ञान है जो सर्वहारा वर्ग के और सभी उत्पीड़ित और शोषित वर्गों के क्रान्तिकारी संघर्ष का मार्गदर्शन करता है और जो समाजवाद और कम्युनिज़्म को समूचे विश्व में विजय की मंज़िल तक ले जाता है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सार्वभौमिक सच्चाई को क्रान्ति के ठोस व्यवहार से जोड़ते हुए, अध्यक्ष माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विरासत हासिल की, इसकी हिफाजत की और इसे विकसित किया। मार्क्सवादी-लेनिनवादी विश्व-दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद है और यह दुनिया को समझने और बदलने का सर्वोत्तम हथियार है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुड. विचारधारा हमें बताती है कि पूंजीवाद का लोप और कम्युनिज़्म की विजय निश्चित है। अन्ततोगत्वा समाजवाद पूंजीवाद की जगह ले लेगा – यह मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र एक वस्तुगत नियम है।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुड. विचारधारा यह भी शिक्षा देती है कि अपनी मुक्ति हासिल करने के लिए, सर्वहारा वर्ग को सशस्त्र बल के द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करना होगा, बुर्जुआ वर्ग की राज्य-मशीनरी को चकनाचूर कर देना होगा, अपना अधिनायकत्व स्थापित करना होगा और उत्पादन के साधनों में निजी सम्पत्ति को समाप्त कर देना होगा तथा साथ ही, उसे समाजवादी क्रान्ति को अन्त तक चलाने के लिए सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत क्रान्ति को जारी रखने पर भी दृढ़ बने रहना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है जिसके जरिए धरती के चेहरे से मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की व्यवस्था मिटाई जा सकती है और हम साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और शोषण की सभी व्यवस्थाओं से मुक्त एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुड. विचारधारा आगे हमें यह शिक्षा देती है कि क्रान्ति को क्रियान्वित करने के लिए एक क्रान्तिकारी पार्टी का होना ज़रूरी है। क्रान्तिकारी संघर्ष में सर्वहारा वर्ग यदि एक वर्ग के रूप में भूमिका निभाना चाहता है, तो इसे अपनी खुद की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी – कम्युनिस्ट पार्टी बनानी होगी। केवल तभी यह व्यापक जनसमुदाय को नेतृत्व दे पाने में, देश के भीतर और बाहर के वर्ग-शत्रुओं पर विजय पाने में और उस महान ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने में, जिसकी जिम्मेदारी इसके कन्धों पर है, समर्थ हो सकेगा।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुड. विचारधारा हमारी पार्टी का सैद्धान्तिक आधार और मार्गदर्शक विचारधारा इसलिए है, क्योंकि यह वस्तुगत यथार्थ से निकलती है और इसने सिद्ध कर दिया है कि इस वस्तुगत जगत में यह सर्वाधिक सही, सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वाधिक क्रान्तिकारी सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है।

सौ वर्षों से भी अधिक समय पहले, सर्वहारा वर्ग के दो महान शिक्षकों – मार्क्स और एंगेल्स ने मार्क्सवाद की रचना की। 1840 के दशक में यूरोप के बहुतेरे देशों में एक उच्च स्तर तक का पूंजीवादी विकास हो चुका था। पूंजीवाद के सभी अन्तर्निहित अन्तरविरोध दिन-प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा तीखे होते जा रहे थे, शोषण और गुलामी की शिकार सर्वहारा आबादी बोझ ढोने वाले जानवरों की ज़िन्दगी बिता रही थी। इन देशों में, मज़दूर आन्दोलन शक्तिशाली रूप से विकसित हो रहा था, सर्वहारा वर्ग इतिहास के मंच पर एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट होने की शुरुआत कर रहा था। लेकिन मज़दूर आन्दोलन वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धान्त स्वतःस्फूर्त ढंग से पैदा नहीं कर सकता था, और काल्पनिक समाजवाद के जो सिद्धान्त उस समय मज़दूर आन्दोलन में बड़े पैमाने पर फैले हुए थे, वे सर्वहारा वर्ग को उसकी मुक्ति का रास्ता नहीं दिखला सकते थे। इन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों में, मार्क्स और एंगेल्स ने, सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्षों की आवश्यक्ताओं को समझते हुए, उस समय के क्रान्तिकारी संघर्षों के व्यवहार में व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा लिया, मज़दूर आन्दोलन के अनुभवों का सार-संकलन किया, सैद्धान्तिक शोध के एक लम्बे और कठिन कार्यक्रम की शुरुआत की, और मानवता की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों में जो कुछ भी तर्कपरक था उसे आत्मसात करते हुए, मार्क्सवाद का सृजन किया। फरवरी, 1848 के महीने में, मार्क्स और एंगेल्स की संयुक्त कृति – **कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र** का प्रकाशन मार्क्सवाद के जन्म का द्योतक था। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने समाजवाद और कम्युनिज़्म की प्रारम्भिक बुनियाद रखने का काम किया। मार्क्स और एंगेल्स ने न केवल सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी सिद्धान्त के सृजन का काम किया, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्षों को नेतृत्व दिया, सभी अवसरवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध लगातार संघर्ष चलाया और मज़दूर आन्दोलन में मार्क्सवाद के व्यापक प्रसार को सम्भव बनाया।

जैसाकि कामरेड स्तालिन हमें बताते हैं: **"लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है"** (*स्तालिन: 'लेनिनवाद के आधार'*)। उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में दुनिया साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग में प्रविष्ट हुई। साम्राज्यवाद और हर किस्म के अवसरवाद के विरुद्ध, विशेषकर दूसरे इण्टरनेशनल के संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान, लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धान्त की विरासत हासिल की, उसकी हिफाजत की और उसे आगे विकसित किया। लेनिन ने साम्राज्यवाद के सभी अन्तरविरोधों का विश्लेषण किया और इसकी प्रतिक्रियावादी प्रकृति को उजागर किया। उन्होंने साम्राज्यवाद के युग में सर्वहारा क्रान्ति के सामने खड़े महत्वपूर्ण सवालों की एक पूरी श्रृंखला का समाधान भी प्रस्तुत किया और साथ ही, एक अकेले देश में सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना से जुड़े सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सवालों को हल किया। यह मात्र एक संयोग नहीं था कि लेनिन के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में रूस में अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति ने महान विजय प्राप्त की और मानवता के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात किया। यही कारण है कि हम मार्क्स और एंगेल्स द्वारा संस्थापित और लेनिन द्वारा विकसित – सर्वहारा क्रान्ति के इस सिद्धान्त को मार्क्सवाद-लेनिनवाद कहते हैं।

अध्यक्ष माओ ने कहा है: **"अक्टूबर क्रान्ति के तोपों की गर्जना ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को हम तक पहुंचाया"** (*माओ त्से-तुड.: संकलित रचनाएं, खण्ड-4 'जनता के जनवादी अधिनायकत्व के बारे में'*)। चीन के क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद के एकीकरण ने चीनी सर्वहारा के हरावल – चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म दिया। अध्यक्ष माओ ने चीनी क्रान्ति के लम्बे व्यवहार के दौरान मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सही ढंग से प्रयोग किया और इसे – चीन में मौजूद अत्यन्त जटिल परिस्थितियों में – अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक विकसित किया। माओ त्से-तुड. विचारधारा क्रान्ति के ठोस व्यवहार के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सार्वभौमिक सच्चाई के एकीकरण की उपज है।

हमारी नई जनवादी क्रान्ति एक विशाल अर्द्धसामन्ती और अर्द्धऔपनिवेशिक देश में सम्पन्न हुई थी। एक ऐसे देश में सर्वहारा वर्ग कैसे क्रान्ति का नेतृत्व कर सका? जैसाकि लेनिन ने कहा था, यह **"एक ऐसा काम (था), जिसका दुनिया के कम्युनिस्टों ने पहले कभी सामना नहीं किया था** (*लेनिन: सम्पूर्ण रचनाएं, खण्ड 30, पूरब के जनगण के कम्युनिस्ट संगठनों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस को सम्बोधन, 22 नवम्बर, 1919*)। अध्यक्ष माओ ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के इतिहास और वर्तमान परिस्थिति का और साथ ही हमारे समाज के प्रमुख अन्तरविरोधों को विश्लेषण किया, तथा हमारे देश में क्रान्ति की प्रकृति, कार्यभारों, प्रेरक शक्ति, उद्देश्यों और भविष्य से जुड़े सवालों का सही उत्तर प्रस्तुत किया। अध्यक्ष माओ ने स्पष्ट किया कि चीनी क्रान्ति अक्टूबर क्रान्ति की निरन्तरता है और कि, यह विश्व सर्वहारा समाजवादी क्रान्ति का एक अंग है। चीनी क्रान्ति दो मंज़िलों में सम्पन्न होनी है: पहली जनवादी क्रान्ति, फिर समाजवादी क्रान्ति। ये भिन्न प्रकृति की दो क्रान्तिकारी प्रक्रियाएं हैं जो एक-दूसरे से पृथक हैं और साथ ही अन्तरसम्बन्धित भी। बुर्जुआ जनवाद की, पहली क्रान्तिकारी प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने की स्थिति में ही, दूसरी प्रक्रिया, यानी समाजवादी क्रान्ति को सम्पन्न कर पाना सम्भव है। जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्ति के ज़रूरी तैयारी है, और जनवादी क्रान्ति के बाद अगली मंजिल अनिवार्यतः समाजवादी क्रान्ति की ही होती है। अध्यक्ष माओ ने यह भी बताया कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्त और कार्यशैली के आधार पर निर्मित एक कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसी पार्टी के नेतृत्व के अन्तर्गत एक सेना, और इस पार्टी के नेतृत्व में सभी क्रान्तिकारी वर्गों और संस्तरों का एक संयुक्त मोर्चा – ये सत्ता पर कब्ज़ा और उसके सुदृढ़ीकरण के तीन मुख्य हथियार हैं। अध्यक्ष माओ ने देहातों में क्रान्तिकारी आधार का निर्माण करने, शहरों को गांवों से घेरने और उसके बाद शहरों पर कब्ज़ा करने के क्रान्तिकारी मार्ग का खाका तैयार किया। ठीक इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, अठ्ठाइस वर्षों के सशस्त्र संघर्ष के बाद, चीनी क्रान्ति ने साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और नौकरशाह पूंजीवाद के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने में और नये चीन की स्थापना में अन्ततोगत्वा कामयाबी हासिल की तथ नई जनवादी क्रान्ति ने सम्पूर्ण विजय हासिल की।

जनवादी क्रान्ति की विजय के

(पेज 5 पर जारी)

पार्टी की बुनियादी समझदारी

(पृष्ठ 4 से आगे)

बाद, हमारा देश समाजवादी क्रान्ति के काल में प्रविष्ट हुआ। समाजवादी समाज में, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के समाजवादी रूपान्तरण के काम के बुनियादी तौर पर पूरा हो जाने के बाद, देश के भीतर कौन से मुख्य अन्तरविरोध हैं? क्या वर्ग, वर्ग-अन्तरविरोध और वर्ग-संघर्ष अभी भी मौजूद हैं? चीनी क्रान्ति के वर्तमान और भावी कार्यभार क्या हैं? अध्यक्ष माओ ने पूरी दुनिया में और हमारे देश में, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अनुभवों का, इसके सकारात्मक और नकारात्मक – दोनों पक्षों का, सार-संकलन किया और **'जनता के बीच के अन्तरविरोधों को सही ढंग से हल करने के बारे में'** शीर्षक एक महत्वपूर्ण रचना प्रकाशित की जिसमें, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विकास के इतिहास में पहली बार, उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से यह दिखलाया कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का समाजवादी रूपान्तरण मुख्यत: सम्पन्न हो जाने के बाद भी, वर्ग, वर्ग-अन्तरविरोध और वर्ग-संघर्ष मौजूद रहते हैं और सर्वहारा वर्ग को अनिवार्यत: क्रान्ति की प्रक्रिया जारी रखनी होती है। 1962 में आठवीं केन्द्रीय कमेटी के दसवें प्लेनरी सत्र में अध्यक्ष माओ ने और अधिक विस्तार के साथ, समाजवाद की समूची ऐतिहासिक अवधि के लिए हमारी पार्टी की बुनियादी लाइन प्रस्तुत की। इस बुनियादी लाइन के मार्गदर्शन में, हमारी पार्टी ने समाजवादी क्रान्ति और समाजवादी निर्माण में और बड़ी जीतें हासिल करने में, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की महान जीतें हासिल करने में, समूचे देश की जनता का नेतृत्व किया है।

हमारे देश में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति समाजवाद की स्थितियों के अन्तर्गत एक महान राजनीतिक क्रान्ति है, जिसके दौरान सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग और सभी शोषक वर्गों का विरोध करता है, अपने अधिनायकत्व को मजबूत बनाता है और पूंजीवादी पुनर्स्थापना को रोकता है।

भविष्य में, समय-समय पर, बार-बार ऐसी क्रान्तियां छेड़नी होंगी। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, अध्यक्ष माओ के नेतृत्व में समूची पार्टी, समूची सेना और समूची जनता ने, ल्यू शाओ-ची और लिन प्याओ के नेतृत्व वाले बुर्जुआ वर्ग के दो हेडक्वार्टरों को तबाह कर डाला – यह देश के भीतर की और पूरी दुनिया की प्रतिक्रियावादी ताकतों के लिए एक करारी चोट थी। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अन्तर्गत क्रान्ति को जारी रखने के अध्यक्ष माओ के सिद्धान्त ने, और उनके व्यक्तिगत पहल पर तथा उन्हीं के नेतृत्व में संचालित महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति ने सर्वहारा क्रान्ति और सर्वहारा अधिनायकत्व के मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त को समृद्ध एवं विकसित किया है। इसलिए, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के लिए यह एक महान अवदान है।

(अगले अंक में जारी)

स्वर्ग का तलघर अंधेरा यहां भी है, वहां भी!
स्वर्ण की मीनार रौशन वहां भी है, यहां भी!

• मीनाक्षी

पूरी दुनिया के ग़रीब देशों की प्राकृतिक सम्पदा और श्रम को निचोड़ने वाले साम्राज्यवादी आदमख़ोर खुद अपने देशों के मज़दूरों के नस-नस से खून निचोड़कर सिक्के ढालने के काम में भी किसी तरह की मुरौव्वत नहीं करते। आये दिन पूंजीवादी अखबारों-पत्रिकाओं में कलम के दल्ले, दिमाग़ के गुलाम इस सच्चाई पर गम्भीर चिन्ता जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूरोप के अन्य देशों में भी बेरोजगारों और बेघरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सामाजिक अपराध, निराशा, मनोरोग और शराबखोरी लगातार बढ़ रही है तथा साथ ही सामाजिक असन्तोष भी लगातार गहराता जा रहा है।

एक ज़माना था जब उपनिवेशों-नवउपनिवेशों और निर्भर, ग़रीब पूंजीवादी देशों की लूट से यूरोप-अमेरिका के पूंजीपतियों ने कुछ टुकड़े घूस के रूप में अपने देश के मज़दूरों के एक हिस्से को देकर उसे सफ़ेदपोश बनाने का तथा मज़दूर आंदोलन को भीतर से कमज़ोर करने के काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। अब स्थिति में कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कुछ बुनियादी बदलाव आये हैं। मुनाफे के हवस में पगलाये साम्राज्यवादी पूंजी के अति संचय की अपच से परेशान हैं। ज्यादा से ज्यादा निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा पूंजी, और फिर उस पूंजी को लगाने की समस्या और ज्यादा से ज्यादा रफ़्तार से मुनाफा कमाकर एक-दूसरे को पीछे छोड़ देने की आपसी होड़। इस समस्या ने आज पूरे ढांचे के बुनियाद को चरमरा दिया है और कई नई-नई समस्याओं को जन्म दिया है।

इन्हीं समस्याओं में से एक यह है कि पश्चिम के धनी देशों में मज़दूरों को जो सहूलियतें हासिल थीं, वे तेजी से छिन रही हैं। सफ़ेदपोश मज़दूरों का तथा बेहतर जीवन स्थिति वाले संगठित कारखानां मज़दूरों का तबका तेजी से सिकुड़ रहा है और आंशिक रोजगार वाले, दिहाड़ी या ठेका पर काम करने वाले मज़दूरों तथा छंटनीशुदा मज़दूरों और बेरोजगारों की संख्या तेजी से फैलती जा रही है। "स्वर्ग" के तलघर में अंधेरा तो हरदम ही था, पर वह एकदम घना हो गया है और तलघर का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में फैला है, जिस अनुपात में समृद्धि की मीनार की ऊंचाई बढ़ती गई है। यूरोप-अमेरिका के मज़दूर एक बार फिर उन्नीसवीं सदी जैसी नारकीय स्थितियों के क़रीब से क़रीबतर पहुंचते जा रहे हैं। और उनसे भी बदतर स्थिति है पूर्व सोवियत संघ के घटक देशों और पूर्वी यूरोप के देशों के मेहनतकशों की जिन्हें "स्वर्ग" का सपना दिखाकर छला गया और ऐसे नर्क में ढकेल दिया गया जहां अंधेरा नकली समाजवाद से भी कई गुना अधिक गहरा और बदबूदार था।

अभी हाल ही में 'ब्रेडलाइन यूरोप' नामक एक संस्था ने यूरोप में ग़रीबी का अध्ययन करते हुए ब्रिटेन के बारे में जो आंकड़े इकट्ठा किये, वे खुद उक्त संस्था के शोधकर्ताओं के लिए ही हैरतअंगेज़ थे। विगत पांच मार्च को लन्दन में प्रकाशित, उक्त संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की 50 लाख से भी कुछ अधिक आबादी फिलहाल अत्यधिक ग़रीबी की दुरवस्था में नर्क़ की ज़िन्दगी बसर कर रही है। ज़िन्दगी की एकदम बुनियादी ज़रूरतों तक से महरूम इस आबादी की जीवन-स्थितियों को "निरपेक्ष ग़रीबी" का नाम देते हुए ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोध कर्ता और उक्त रिपोर्ट के सह सम्पादक डेविड गोर्डन ने कहा, "हम तो एकदम दंग रह गये ... हम उम्मीद कर रहे थे ग़रीबों की एक छोटी सी आबादी की ... इतनी भारी तादाद के बारे में तो हमने सोचा तक नहीं था। कल्याणकारी राज्य के सुरक्षा-जाल से बाहर फिसल चुके लोग जिस ग़रीबी में धंसे हुए हैं, हमें उसकी गहराई का अहसास तक नहीं था।"

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, नौ प्रतिशत ब्रिटिश परिवारों की आमदनी इतनी कम है कि वे निरपेक्ष ग़रीबी के नीचे की ज़िन्दगी बिता रहे हैं (1995 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भोजन, साफ पानी, साफ-सफाई की सहूलियतों, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, शिक्षा और सूचना के अभाव को 'निरपेक्ष ग़रीबी' की अवस्था के रूप में परिभाषित किया था)। इस नौ प्रतिशत से ऊपर, आठ प्रतिशत ब्रिटिश परिवारों की आय "ज़रूरी स्तर से थोड़ी नीचे" है। दो वर्षों से भी कुछ अधिक समय में तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में कल्याणकारी सुविधाएं अब सिकुड़कर उस स्थिति से काफी नीचे आ चुकी हैं, जो निरपेक्ष ग़रीबी की स्थिति न पैदा होने देने के लिए ज़रूरी है।

अभी पिछले दस वर्षों के दौरान अमेरिका के अश्वेत और आप्रवासी लातिनी मज़दूरों की नारकीय जीवन स्थितियों और पुलिस-दमन पर काफी रिपोर्टें छप चुकी हैं। अब बेरोजगार श्वेत युवाओं और मज़दूरों का बड़ा हिस्सा भी वैसी ही स्थिति में पहुंचता जा रहा है। जर्मनी के पश्चिमी हिस्से में जाकर पेट पालने वाले पूर्वी जर्मन मज़दूरों की स्थिति भी आप्रवासी कुर्द और तुर्क मज़दूरों जैसी ही है।

और यही कारण है कि मज़दूरों और मेहनतक़शों के असंतोष के जनज्वार आज यदि भारत, मेक्सिको, अर्जेण्टीना, फिलिप्पींस आदि देशों में फूट रहे हैं तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि देशों की सड़कों पर भी मज़दूर प्रदर्शनों और आन्दोलनों का सैलाब एक बार फिर उमड़ता दीख रहा है।

लुटेरों की एकता आज यदि दुनिया के पैमाने पर क़ायम है तो मेहनतक़शों की विश्वव्यापी एकजुटता की भी एक सर्वथा नई ज़मीन तैयार हो रही है।

27 सार्वजनिक उपक्रमों की बोली लगेगी

दिल्ली। सरकारी कम्पनी बाल्को (भारत एल्युमिनियम कम्पनी) के 51 प्रतिशत शेयर निजी कम्पीन स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हाथों सिर्फ 551 करोड़ रुपये में बेच देने में कामयाब होने से उत्साहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने 27 और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बोली लगाकर सरकारी घाटा कम करने की योजना बना ली है। भारत सरकार के विनिवेश विभाग (निजीकरण विभाग) ने जो सूची बनायी है, उसके मुताबिक इस वर्ष जुलाई तक एअर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स, विदेश संचार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., सी.एम.सी.लि.,

हिन्दुस्तान जिंक लि., आई.बी.पी.लि. को पूंजीपतियों के हाथों बेच देना है। इसके अलावा जिन कम्पनियों का नाम इस सूची में है वे हैं -- इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पर्यटन विकास निगम, हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लि., हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स एण्ड केमिकल्स लि., मद्रास फर्टीलाइजर्स लि. तथा इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड शामिल हैं।

बजट पेश करने के अगले दिन देश के चोटी के मुनाफाखोरों को यशवन्त सिन्हा ने आश्वासन दिया कि सिर्फ कुछेक नाजुक रणनीतिक मामलों को छोड़कर सभी सार्वजनिक उपकमों को बेच दिया जायेगा।

इस वित्त वर्ष के अन्त तक इन उपकमों की बिकी से सरकार 12000 करोड़ रुपये कमाना चाहती है। पिछले चार वर्षों में अब तक सरकार लगभग 183 अरब 93 रुपये जुटा चुकी है। सरकार इस धीमी रफ्तार से हो रही बिक्री से सन्तुष्ट नहीं है। इसलिए इस बजट के बाद उसने जोर का झटका लगाने की ठान ली है।

परिकल्पना प्रकाशन की प्रस्तुति

माँ

मक्सिम गोर्की

वास्तविक घटनाओं पर आधारित **1905-7 की पहली रूसी क्रान्ति के समय** लिखी गई और समूची दुनिया के पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय पुस्तक **गोर्की** की यह पुस्तक महज एक मज़दूर परिवार की नियति का चित्रण करने के बजाय समूचे सर्वहारा वर्ग के भविष्य को विलक्षण शक्ति के साथ चित्रित करती है।

मूल्य : 70 रुपये

प्राप्त करें :

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020

फोन : 788932

अक्टूबर क्रांति की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर राहुल फाउण्डेशन की नई प्रस्तुति

अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन

सोवियत समाजवादी क्रान्ति की तैयारी से लेकर बाद के दौर तक वहां उपस्थित रहकर युगान्तरकारी घटनाओं के साक्षी रहे अमेरिकी पत्रकार एल्बर्ट रीस विलियम्स की दो दुर्लभ कृतियां :

'रूसी क्रान्ति के दौरान' तथा **'लेनिन : व्यक्तित्व और कार्य'** एक ही जिल्द में हिन्दी पाठकों के लिए विशेष रूप से

साथ ही रीस विलियम्स का परिचय

मूल्य : रु. 75/- (पेपर बैक) रु. 150/- (साजिल्द)

एल्बर्ट रीस विलियम्स की कृतियां क्रान्तिकारी दौर की घटनाओं में उनके असली नायक आम जन समुदाय के कारनामों और सोच को सामने लाती है तथा लेनिन के मानवीय, जीवन्त और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का प्रामाणिक प्रभावी चित्र प्रस्तुत करती है जिनके साथ उन्हें लम्बे समय तक रहने का अवसर मिला था।

प्राप्त करें :

जनचेतना

डी-68, निराला नगर, लखनऊ-226 020

जनमुक्ति की अमर गाथा: चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-बारह)

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति : एक युगान्तरकारी प्रयोग

1. माओ त्से-तुङ. : महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के मार्गदर्शक, नेता और सिद्धान्तकार

(1)

समाजवादी शिक्षा आन्दोलन के लक्ष्य को पराजित करने के लिए पार्टी के भीतर एक संशोधनवादी गिरोह लगातार सक्रिय था, जो चीन को वास्तव में ख्रुश्चेव के रास्ते पर ले जाना चाहता था, लेकिन व्यापक जनता में माओ के सम्मान और उनकी लाइन की स्वीकार्यता को देखते हुए, खुलकर सामने आने के बजाय तिकड़म और षडयन्त्र का तरीका अपना रहा था। इसी गुट ने पहले 'महान अग्रवर्ती छलांग' को भी बदनाम करने और विफल बनाने की कोशिशें की थीं। पार्टी और राज्य के नौकरशाहों, बुद्धिजीवियों और भूतपूर्व शोषकों के बीच इनका सामाजिक आधार था और जनता की पिछड़ी चेतना का भी ये लोग अपने पक्ष में इस्तेमाल करते थे। समाजवादी शिक्षा आन्दोलन द्वारा जनता को उन्नत समाजवादी चेतना देने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ल्यु शाओ ची ने 'चार स्वच्छ बनाम चार अस्वच्छ' नामक नया निर्देश जारी किया।

पूंजीवादी नीतियों के विरुद्ध केन्द्रित वर्ग संघर्ष की दिशा मोड़ देने की इस कोशिश के खिलाफ जनवरी 1965 में माओ ने 'ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी शिक्षा आन्दोलन में उभरी कुछ सामयिक समस्याएं' नामक दस्तावेज लिखा जो 23 सूत्री दस्तावेज के नाम से प्रसिद्ध है। इस दस्तावेज में पहली बार माओ ने स्पष्ट बताया कि आन्दोलन का मुख्य निशाना केवल नौकरशाह, भ्रष्ट तत्व और गलतियां करने वाले लोग ही नहीं हैं बल्कि मुख्यत: "ऊंचे पदों पर आसीन वे पार्टी सदस्य हैं जिन्होंने पूंजीवाद का रास्ता अपनाया है", जिन्होंने स्वार्थवाद, व्यक्तिवाद, निजी उद्यम और व्यक्तिगत हित को बढ़ावा दिया है तथा मिल्कियत, उत्पादन और विनिमय की समाजवादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। इस दस्तावेज में पहली बार एक कार्यदिशा प्रस्तुत की गयी जिसे सांस्कृतिक क्रान्ति ने और अधिक ठोस एवं स्पष्ट किया तथा अमल में उतारा। दस्तावेज में स्पष्ट कहा गया था कि पार्टी के भीतर के पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए और पार्टी को दोषमुक्त बनाने के लिए उनके खिलाफ तमाम जन संगठनों और पार्टी की आम कतारों को लामबन्द करना होगा तथा मज़दूर वर्ग और पूंजीपतियों के बीच दो लाइनों का संघर्ष

4. केन्द्रीय ललित कला अकादमी की माध्यमिक कक्षाओं के छात्र क्रान्तिकारी पोस्टर तैयार करते हुए 1966

छेड़ना होगा जो क्रान्ति के भाग्य का निर्णय करेगा।

(2)

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की शुरुआत का संकेतक पहला गोला 10 नवम्बर, 1965 को दगा, जब माओ की लाइन के समर्थक याओ वेन युआन ने 'हाई जुई दफ्तर से बर्खास्त हुआ' नाटक की आलोचना करते हुए शंघाई के एक दैनिक अखबार में एक लेख लिखा। पेकिङ. के उपमेयर वु हान द्वारा लिखित इस नाटक में मिङ. राजवंश काल की एक कहानी की आड़ लेकर वास्तव में माओ द्वारा 1959 में संशोधनवादी पेङ.-तेह-हुआई की बर्खास्तगी की आलोचना की गई थी और देहातों में जन कम्यूनों के निर्माण की माओ की नीति पर हमला किया गया था। यह लेख तीन सप्ताह बाद, बड़ी मुश्किल से 'पीकिङ. दैनिक' में प्रकाशित हो सका, क्योंकि राजाधानी के सत्ता केन्द्रों पर संशोधनवादी गुट की पकड़ काफी मजबूत थी। यहां तक कि सांस्कृतिक क्रान्ति को नेतृत्व देने के लिए पांच का जो ग्रुप बनाया गया था, उसमें काङ. शेङ. को छोड़कर सभी संशोधनवादी थे और ग्रुप का नेता, पीकिङ. का मेयर पेङ. चेन स्वयं उनका सरगना था।

जनवरी, 1966 में पीकिङ. रिव्यू ने यह घोषणा की : "सत्ता से बाहर किये गये पूंजीवादी, पुनर्बहाली और तोड़फोड़ की अपनी साजिशों में हमेशा विचारधारा को सबसे आगे रखते हैं, विचारधारा और ऊपरी ढांचे पर कब्जा जमाते हैं। पूंजीपतियों के प्रतिनिधि अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करके कई विभागों के नेतृत्व को छीनकर नियंत्रित करते हैं, साहित्य, थियेटर, फिल्मों, संगीत, कला, प्रेस, पत्रिकाओं, रेडियो, प्रकाशनों और विद्यालयों में शैक्षिक शोध आदि के माध्यम से, उनसे जितना बन

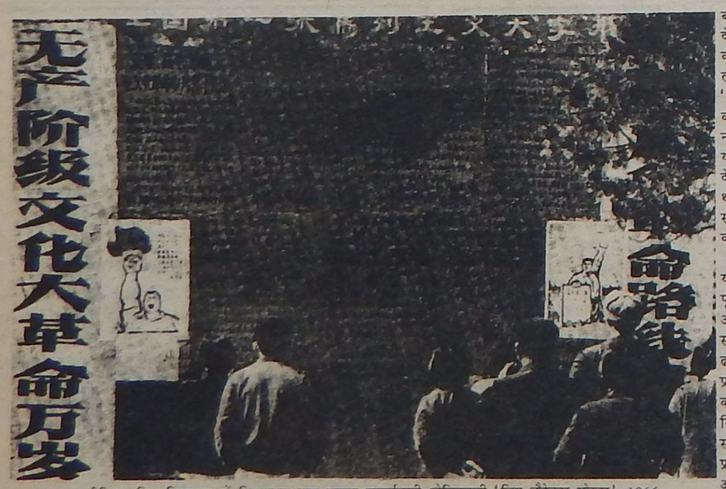

2. पीकिङ. विश्वविद्यालय में चिपकाया गया पहला मार्क्सवादी-लेनिनवादी 'बिग कैरेक्टर पोस्टर', 1966

3. सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान तिएन-एन-मेन चौक पर क्रान्तिकारी जनसमुदाय की एक सभा में माओ त्से-तुङ. 1966

16 मइ सर्कुलर ने पार्टी के भीतर के उन प्रतिक्रान्तिकारी तत्वों को पहचानने का आहवान किया जो "सर्वहारा अधिनायकत्व को बुर्जुआ अधिनायकत्व में बदल देना" चाहते थे। सर्कुलर ने सांस्कृतिक क्रान्ति का विरोध करने वाले नेताओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए पार्टी सदस्यों का आहवान किया। केन्द्रीय कमेटी ने पेङ. चेन के नेतृत्व वाले पांच के ग्रुप को भंग कर दिया और ग्रुप की रिपोर्ट धोखेबाजी से केन्द्रीय कमेटी के नाम से छापने के लिए पेङ. चेन कोक कड़ी फटकार लगाई।

इसी बीच 25 मई को पीकिङ. विश्वविद्यालय के सात युवा प्राध्यापकों ने एक बड़े चित्राक्षरों वाला पोस्टर (बिग कैरेक्टर पोस्टर) निकाला जिसमें पीकिङ. विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और पेकिङ. पार्टी कमेटी के एक सदस्य की, छात्र आन्दोलन का दमन करने और पार्टी कमेटी के कुछ वरिष्ट सदस्यों का बचाव करने के लिए आलोचना की गई थी। एक सप्ताह बाद माओ को जब इस पोस्टर के बारे में पता चला तो आम जनता द्वारा उच्च पदस्थ लोगों की आलोचना के अधिकार का समर्थन करते हुए उन्होंने उक्त पोस्टर को अखबारों में छापने और रेडियो से ब्राडकास्ट करने के निर्देश जारी किये।

इसके बाद पूरे देश में विद्रोही छात्रों द्वारा ऐसे 'बिग कैरेक्टर पोस्टर' चिपकाने का तांता-सा लग गया। प्राय: ये पोस्टर बहुत रचनात्मक होते हो और इनमें पार्टी नौकरशाहों और उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए राजनीतिक मुद्दों को रेखांकित किया जाता था। माओ ने कहा कि सभी अधिकारियों को इन पोस्टरों को पढ़ना चाहिए और केवल क्रान्ति विरोधी तत्व ही इनसे भयभीत होंगे।,

पार्टी ने छात्रों के इस व्यापक जनान्दोलन को नेतृत्व और दिशा देने के लिए कार्यदलों का गठन किया और उन्हें

7. याङ.त्सी नदी में माओ की प्रसिद्ध तैराकी, जुलाई 1966

छात्रों के बीच भेजा गया। इस बीच माओ पीकिङ. से बाहर चले गये। राजधानी में शीर्ष नेता के रूप में ल्यु शाओ-ची और केन्द्रीय कमेटी के तत्कालीन महासचिव देङ.सियाओ-पिङ. ही बचे रहे। मौके का लाभ उठाकर उन्होंने अपने गुट के सहारे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करके उस व्यापक उभार का गला घोंटना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए वे लगातार माओ के नाम का इस्तेमाल करते रहे और उनके हवाले देते रहे, जिसके बारे में बाद में माओ ने कहा कि "वे लाल झण्डा लहराते हुए लाल झण्डे का विरोध कर रहे थे।" इससे जनता में काफी भ्रम फैला। नेतृत्व देने के लिए भेजे गये कार्यदलों ने छात्रों के बीच फूट और गुटबाजी को खूब बढ़ावा दिया और उन्हें आपस में ही लड़ा दिया।

जुलाई के अन्त में जब माओ पीकिङ. लौटे तो देखा कि सांस्कृतिक क्रान्ति आंशिक रूप से मर रही थी। ल्यू-देङ. गिरोह के पीछे एकजुट नौकरशाह जनता के उत्साह और पहलकदमी को काफी हद तक तोड़ चुके थे और क्रान्तिकारी युवाओं में फूट डाल चुके थे। सब कुछ एकबार फिर नये सिरे से शुरू करना था।

(4)

माओ का लक्ष्य यदि महज पार्टी-नेतृत्व पर हावी मुट्ठी भर पूंजीवादी पथगामी होते तो वे उन्हें आसानी से बाहर निकाल सकते थे क्योंकि पूरे देश की जनता में और पार्टी कतारों में उनका व्यापक सम्मान था। पर उनका विचार था कि नेतृत्व के इस छोटे-से हिस्से की पूंजीवादी नीतियों का व्यापक सामाजिक आधार है अत: इन विचारों को यदि जड़ से नहीं उखाड़ा गया तो ये पार्टी में बार-बार सिर उठाते रहेंगे। उनका कहना था कि सांस्कृतिक क्रान्ति व्यापक तौर पर एक जन-क्रान्ति है, जो न केवल भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ना, बल्कि सदियों पुराने मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं, पूंजीवादी चिन्तन एवं संस्कृति तथा समूह के ऊपर "मैं" की प्रधानता को मिटाना चाहती है। ये पिछड़े विचार सहकारिताओं, कम्यूनों और राजकीय उद्यमों में हो रहे उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ-साथ हो रहे

शेष आठ पर जारी

5. सांस्कृतिक और शिक्षा-क्षेत्र के कार्यकर्ता पीकिङ. में उच्च पदों पर आसीन पूंजीवादी पथगामियों की आलोचना करते हुए 1966

सकता है, पूंजीवादी और संशोधनवादी ज़हर फैलाते हैं। जनता के दिमागों को दूषित करने के प्रवास में "शांतिपूर्ण संक्रमण" की विचारधारात्मक प्रस्तुतियां करते हैं और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए जनमत बनाने की तैयारी करते हैं।"

6 फरवरी, 1966 को पेङ. चेन ने समाजवादी शिक्षा विषयक एक परिपत्र जारी किया जिसमें क्रान्तिकारी लाइन के दो नेताओं – चाङ. चुन-चियाओ और याओ वेन-युआन की आलोचना की गई थी। लेकिन उक्त परिपत्र की अवहेलना करके उन दोनों ने अपनी मुहिम जारी रखी।

(3)

अप्रैल के अन्त में माओ पीकिङ. लौटे। केन्द्रीय कमेटी की एक तूफानी बैठक में स्वीकृति के बाद पेङ. चेन के परिपत्र को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक परिपत्र जारी हुआ जो '16 मई सर्कुलर' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस परिपत्र में यह साफ-साफ बताया गया था कि "ख्रुश्चेव की तरह के लोग ...हमारी बगल में चिपट कर बैठे हैं।"

6. तिएन-एन-मेन चौक पर रेड गार्डों कीएक रैली 1966

जनमुक्ति की अमर गाथा: चीनी क्रान्ति की सचित्र कथा (भाग-बारह)

पेज सात से आगे

राह के रोड़े बन जाते हैं और अन्ततः उत्पादक शक्तियों के विकास का रास्ता भी बंद कर देते हैं जिससे चीज़ों को निजी स्वामित्व की ओर पीछे लौटा देना संशोधनवादियों के लिए सुगम हो जाता है।

जून से लेकर मध्य जुलाई 1966 तक पीकिड. से बाहर मध्य चीन में प्रवास करते हुए माओ राजधानी के पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थे और आगे के कठिन संघर्ष की तैयारियों में लगे हुए थे। 16 जुलाई की सुबह वुहान शहर में याड.त्सी के किनारे दो लाख लोगों की उपस्थिति में माओ उपस्थित हुए। 1956 के बाद हर वर्ष इसी समय याड.त्सी तैरकर पार करना एक वार्षिक आयोजन बन चुका था। इस बार माओ का याड.त्सी तैरकर पार करना एक प्रतीकात्मक संकेत बन गया था। यह संकेत था कि सांस्कृतिक क्रान्ति के प्रचण्ड ज्वार में कूद पड़ने और करोड़ों युवाओं-मेहनतकशों का नेतृत्व करने के लिए 'चिरयुवा' माओ एकदम तैयार थे। उनके साथ हज़ारों युवा नदी में कूद पड़े और किनारे खड़ा विशाल जनसमुदाय जोशीले नारे लगाता रहे। पूरे देश की जनता में यह संदेश गया कि नई क्रान्ति की अगुवाई करने के लिए 'पुराना नेता' एकदम चुस्त-दुरुस्त है और बुढ़ापे से उसका शरीर और आत्मा अछूती है।

अगले ही दिन माओ पीकिड. पहुंचे और एक उच्चस्तरीय पार्टी-बैठक में उन्होंने कार्य-दलों की खुली और कठोर आलोचना की। 1 अगस्त को उन्होंने पीकिड. स्थित सिनहुआ विश्वविद्यालय के छात्रों को एक व्यक्तिगत पत्र में लिखा: "तुम लोग कहते हो कि प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध विद्रोह न्यायसंगत है। मैं उत्साहपूर्वक तुमलोगों का समर्थन करता हूं।" साथ ही उन्होंने अतिरेक की गलतियों से बचने के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हुए यह भी लिखा कि गलतियां इंगित किये जाने के बाद, गम्भीर गलतियां करने वालों को भी अपने को ठीक करने का एक मौक़ा दिया जाना चाहिए।

जल्दी ही स्कूलों के कैम्पसों में कार्यदलों का विरोध करने के लिए छात्रों के छोटे-छोटे ग्रुप संगठित होने लगे। जुलाई के अंत में पीकिड. विश्वविद्यालय से जुड़े एक हाई स्कूल में पहला 'रेड गार्ड ग्रुप' संगठित हुआ। एक महीने के भीतर पूरे देश के स्कूलों में हज़ारों ऐसे रेड गार्ड ग्रुप बन गये जिनमें दसियों लाख युवा शामिल थे।

पूरे देश में मानो बिजली की लहर सी दौड़ गयी। कारख़ानों से बाहर निकलकर मज़दूर भी रोजाना के जन-प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। गांवों से किसान अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर शहरों के विश्वविद्यालयों में पहुंचने लगे। छात्र उनको पूरी स्थिति से परिचित कराते थे और उनसे अपने विचार रखने को कहते थे।

एक ओर तो लाखों लोग पीकिड. की ओर उमड़ रहे थे, उसी समय रेड गार्ड युवा सांस्कृतिक क्रान्ति का सन्देश लेकर देश के कोने-कोने के सुदूर देहाती इलाकों की ओर कूच करने लगे।

माओ ने छात्रों का आह्वान किया कि वे पूरे देश की किसान-मज़दूरों से सम्पर्क करके उन्हें सांस्कृतिक क्रान्ति के उद्देश्य और ज़रूरत के बारे में बतायें, उनके अनुभव और उनकी राय से परिचित हों तथा पार्टी नेताओं की सही पहचान करने और पूंजीवादी पथगामियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें लामबन्द करें।

युवा क्रान्तिकारी बसों और ट्रेनों से यात्रा करके तथा छः-छः सौ मील तक पैदल अभियान चलाकर लोगों को पूरी स्थिति बताई, उनके बीच पार्टी-दस्तावेज और माओ के उद्धरणों की 'लाल किताब' बांटी तथा भ्रष्ट पार्टी नौकरशाहों के खिलाफ 'बिग कैरेक्टर पोस्टर' लिखिने और उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जनता का आह्वान किया। अक्सर रेड गार्डों ने अति उत्साह की ग़लतियां भी कीं और ग़लत लोग निशाना भी बने। पर माओ को इसका पूर्वानुमान था कि इतने बड़े जनान्दोलन में ग़लतियां स्वाभाविक थीं। उनका कहना था कि विद्रोही युवा लोग ग़लतियां करेंगे, ठोकर खायेंगे और फिर उनसे सीखेंगे। रेड गार्डों के दस्तों ने अपने मुख्य काम के साथ-साथ गांवों में पुरातनपंथी विचारों और संस्कृति के विरुद्ध भी व्यापक मुहिम चलाई। भारी संख्या में स्त्रियों को भी उन्होंने सामाजिक कार्यों और आन्दोलन में भागीदारी के लिए संगठित किया और पुरुष सत्तात्मक मूल्यों के विरुद्ध जबर्दस्त जनजागृति पैदा करने का काम किया।

(अगले अंक में जारी)

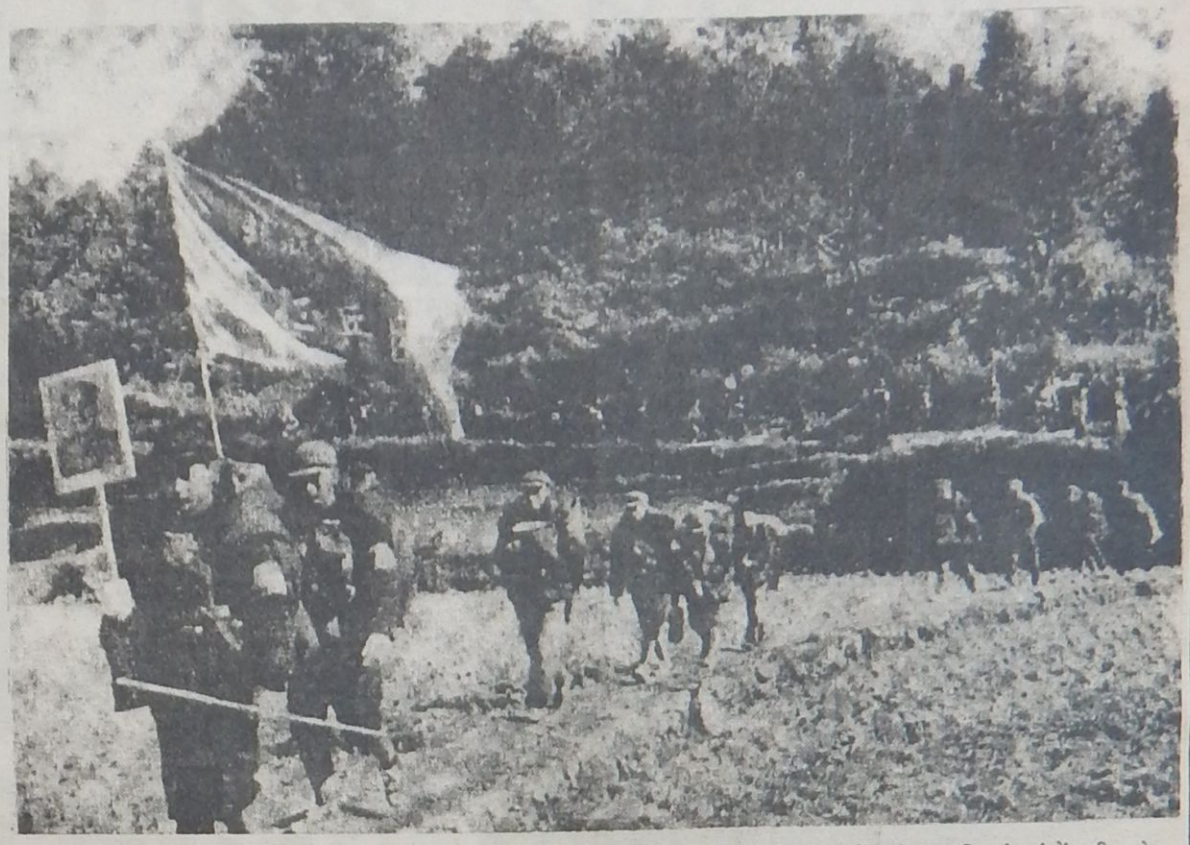

8. किसानों को सांस्कृतिक क्रान्ति की धारा से जोड़ने के लिए पीकिड. से रेड गार्डों की टुकड़ियां गांवों की ओर कूच करती हुई 1966

9. दूर-दूर से आये किसान-मज़दूर विश्वविद्यालयों में 'बिग कैरेक्टर पोस्टर' पढ़ते थे और छात्रों से विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करते थे।

10. स्वयं माओ द्वारा तैयार किया गया 'बिग कैरेक्टर पोस्टर' – 'बुर्जुआ हेडक्वार्टरों को तबाह कर दो', 5 अगस्त, 1966

11. माओ के पोस्टर के साथ रेड गार्ड छात्राएं 1966

यह सौदा महंगा पड़ेगा

पेज एक से आगे

सौदेबाजी में यह कम्पनी उस्ताद जो है!)

यशवन्त सिन्हा के इस सौदे से सभी हाकिम लोग खुश हैं। टाटा-बिड़ला खुश, अम्बानी खुश और उनकी समूची देशी-विदेशी बिरादरी खुश। इस बार स्वदेशी लाला राहुल बजाज भी खुश हैं। सब उन्हें बधाई दे रहे हैं। जब अमेरिकी राजदूत फ्रैंक वाइजनर भी खुश हैं तो फिर रंगाखुश! इन सबकी खुशियों से गदगद यशवन्त अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और मेहनतकश जनता को उपदेश पिलाते घूम रहे हैं। उनकी धमकी भरी नसीहत है कि भूल जाओ पुराने दिन जब तुम लोग सरकारी टुकड़ों पर पलते थे। बस्स! बहुत हो चुका। अब राशन की प्रणाली खत्म, पेंशन खत्म, सरकारी नौकरी खत्म। सस्ती खाद-पानी-बिजली-पढ़ाई, दवाई बन्द। यानी हर तरह की सरकारी ''मदद-खैरात'' बन्द। अपनी देह और दिमाग की ताकत को खुले बाजार में बेचने की औकात हो तो बेचकर जिन्दा रहो, नहीं तो भाड़ में जाओ। कोई सुनवाई नहीं होगी। कहीं भी नहीं। न सरकार के दरबार में, न कोर्ट-कचहरी में। देशी-विदेशी पूंजीपति ही इस धरती के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं, उनके चरणों में सीस नवाओ। यही नसीहत पिलाते वित्त मंत्री यहां-वहां घूम रहे हैं।

जी हां, यशवन्त सिन्हा का 'न्यू डील' यही है! आइये, इस सौदे की थोड़ी तफसील से छानबीन करें!

देश की मेहनतकश जनता के खून-पसीने से खड़े किये गये तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हाथों औने-पौने दाम बेच देने की शुरुआत तो तभी से जारी है जब से निजीकरण-उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है। लेकिल इस बार यशवन्त सिन्हा ने जिस ढिठाई से इसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है इससे यही पता चलता है कि अब अपने देशी-विदेशी आकाओं की मर्जी को पूरा करने के लिए हर मजबूरी का फन्दा काटने के लिए वह रणतत्पर हो गये हैं। बजट में बिजली बोर्डों के निजीकरण का खाका पेश किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उद्योगों का निजीकरण करने की घोषणा की गयी। इन उद्योगों को कौड़ियों के मोल पूंजीपतियों के हाथ बेचने से जो पैसा आयेगा सरकार उससे अपना घाटा पूरा करेगी। बजट के इस फैसले से अब छंटनी-तालाबंदी-बेकारी की नयी आंधी चलेगी।

मजदूर वर्ग पर सबसे खतरनाक हमला उस प्रस्ताव के जरिये किया गया है जिसमें 1000 से कम मजदूरों वाली औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी मर्जी से जब चाहे किसी मजदूर को निकाल सकते हैं।

सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। (देखें बॉक्स)। इसके अतिरिक्त बीमार औद्योगिक कम्पनी कानून और कम्पनी कानून को निरस्त करने की पेशकश भी कर दी गयी है, जिससे कम्पनी को मनमर्जी से कभी भी बन्द कर मालिकान पल्लू झाड़ सकें।

> **जीना महंगा मौज-मस्ती सस्ती**
>
> वर्ष 2001-2002 के केन्द्रीय बजट में कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, स्कूटर-मोटरसाइकिलें और कारें पेप्सी-कोक आदि कई चीजें, जिनका इस्तेमाल मुट्ठी भर धनी तबका करता है, सस्ती कर दी गयी हैं, जबकि, चीनी, चाय की पत्ती, खाने के तेल, रेडीमेड कपड़े आदि कई जीवनोपयोगी चीजें महंगी कर दी गयी हैं। इन उपायों से साफ जाहिर है कि यशवन्त सिन्हा एंड कम्पनी समाज के किन तबकों के लिए भूमण्डलीकरण के फल चखा रही है। जीना महंगा होता जा रहा है और मौज-मस्ती सस्ती होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त यशवन्त सिन्हा ने देशी बड़े पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, सटोरियों और विदेशी निवेशकों को तरह-तरह के कीमती तोहफे भेंट कियं हैं। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची में इस बार फिर कटौती की गयी है। चमड़े से बनने वाले सामानों-- जूते, बैग, खिलौने आदि के 14 मदों को इस सूची से निकालकर बड़े उद्योगों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। इससे अब बाटा, लिबर्टी, रीबोक, एडिडास और नाइकी जैसी कम्पनियों की लूटपाट के लिए और बड़ा इलाका मिल गया है। इन क्षेत्रों के लघु उद्योगों में काम कर रहे लाखों मजदूरों की रोजी छिन जायेगी और वे सड़कों पर आ खड़े हुए करोड़ों मजदूरों की कतार में जा खड़े होंगे।

वित्त मंत्री महोदय ने बजट में टेक्सटाइल क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आयात शुल्कों में जो कमी की है उसका अधिकांश लाभ इस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मिलेगा। इसी तरह देश के भीतर जो बहुराष्ट्रीय निगम कार बना रहे हैं उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए उन्होंने पुरानी कारों व स्कूटरों के आयात पर भारी शुल्क बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं यशवन्त सिन्हा ने कार और स्कूटर निर्माताओं को विशेष उत्पाद शुल्क में 8 प्रतिशत की छूट भी दे दी है। विशेष रूप से यह राहुल बजाज की स्वदेशी लॉबी को दिया गया बेशकीमती तोहफा है! अन्य बहुराष्ट्रीय निर्माता तो अपनी कारों-मोटर साइकिलों की कीमतें घटाकर इससे मुनाफा बटोरेंगे ही।

विदेशी निवेशकों को बजट में इस बार भी तोहफा दिया गया है। विदेशी निवेशक अब किसी भी कम्पनी की पेड अप पूंजी के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गैर बैंकिंग फाइनेंस कम्पनियों में शत-प्रतिशत निवेश कर सकते हैं।

देशी-विदेशी पूंजीपतियों का बेलगाम लूट के लिए दिये गये इन तमाम मौकों के साथ-साथ इस बार अलग-अलग प्रत्यक्ष करों में भी देशी पूंजीपतियों को भारी छूटें देकर मालामाल होने का भरपूर मौका दिया है। (देखें बाक्स - छप्पर फाड़ शैली...)

एक और तरीके से बजट में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की जुगत भिड़ायी गयी है। बजट में छोटी बचतों और भविष्य निधि खातों पर ब्याज दरों में एक से डेढ़ प्रतिशत पर ब्याज में कटौती कर सरकार अपना भूखा पेट भरना चाहती है। हर सरकारी कर्मचारी यह बात जान गया है कि सरकार भविष्य निधि खाते का पैसा निकालकर आजकल अपने खर्चे का बोझ हल्का कर रही है।

मेहनतकश अवाम की जिन्दगी को और तकलीफदेह बनाने वाले तमाम फैसलों में एक फैसला यह भी है कि भारतीय खाद्य निगम अब खाद्यान्नों की खरीद नहीं करेगा। केन्द्र सरकार ने इस काम से हाथ खींचकर अब राज्य सरकारों के मत्थे मढ़ दिया है। इसी के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है। खाद्यान्न भंडारण में निजी क्षेत्र के लिए दी गयी छूटों के साथ अगर इनको जोड़कर देखा जाये तो बात साफ हो जायेगी कि इसके पीछे मंशा क्या है? गरीब आबादी को राशन की दुकानों से जो थोड़ा-बहुत सस्ता राशन मिल जाता है, वह पूरी तरह खत्म करने का आखिरी फैसला।

अगले चार-पांच वर्षों में सरकार हर तरह की सब्सिडी से अपना पिण्ड छुड़ा लेने का मन बना चुकी है। इसकी रूपरेखा बजट में पेश की गयी है। मार्च 2002 तक पेट्रोलियम पदार्थों पर हर तरह की सब्सिडी खत्म करना, अप्रैल 2006 तक चरणबद्ध ढंग से यूरिया पर सब्सिडी खत्म करना, अगले वर्ष चीनी में वायदा कारोबार लागू करना और फिर चीनी की खरीद-बिक्री पर पूरा सरकारी नियंत्रण हआ लेना और दवाओं के मूल्य पर सरकारी नियंत्रण पूरी तरह खत्म कर बाजार के हवाले करना। इन सारे कदमों का सीधा अर्थ यही है मेहतनकश जनता राशन-पानी से लेकर दवा आदि जीवन की हर बुनियादी चीज के लिए बाजार की बेरहम शक्तियों के रहमोकरम पर छोड़ देने का रास्ता पूरी तरह साफ।

सरकारी कर्मचारियों पर बजट की जबर्दस्त मार पड़ी है। सरकारी मकानों के किराये में 15 से 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। अगले दो वर्ष तक के लिए अवकाश यात्रा रियायत न देने का फैसला है। इतना ही नहीं, अब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर भी बन आयी है। पेंशन की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी गयी है जो तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकारी दफ्तरों में छंटनी के सिलसिले को भी अब रफ्तार पकड़ाने का फैसला है। हर वर्ष दो प्रतिशत कर्मचारियों की छुट्टी की जायेगी। इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) के चारे में फंसाकर बाहर करने की पूरी योजना तैयार कर ली गयी है।

इस बजट में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला यह भी हुआ है कि बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को जुलाई 2001 तक पूरी तरह खत्म कर नयी भर्ती का अधिकार सीधे अब बैंकों को दे दिया गया है। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों की एक अच्छी-खासी आबादी को अब तक हर साल बैंकों में रोजगार के अवसर मिल जाते थे, लेकिन बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की नीति और इस फैसले के बाद ये अवसर लगभग खत्म हो जायेंगे।

बजट में शिक्षा के बाजारीकरण की दिशा में और धनिकों के लाड़लों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कई नये कदम उठाये गये हैं। प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मदों

शेष पेज दस पर

> **बजट के जरिये श्रम क़ानूनों में ख़तरनाक बदलाव**
>
> वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तावों के माध्यम से पूंजीपतियों के श्रम कानूनों में बदलाव की मंशा एक हद तक पूरी कर दी हैं चोर दरवाज़े से पहले से ही सीमित मज़दूरों के अधिकारों पर अंकुश लगाने वाला प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस फैसले से लाखों मज़दूरों के भविष्य पर एक और ताला लग जायेगा। यह संभवतः पहली घटना है जबकि बजट प्रस्तावों के जरिए इतना बड़ा फैसला सरकान ने लिया है।
>
> वर्ष 2001-02 के बजट के माध्यम से वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने श्रम क़ानूनों में दो बड़े फेरबदल की घोषणा की है। इससे एक तो कारखानेदारों को मज़दूरों की छंटनी, ले-आफ़ और कम्पनी बन्द करने की खुली छूट मिल जायेगी, दूसरे इन्हें ठेका प्रणाली से काम करवाने की पूरी आज़ादी मिल जायेगी।
>
> वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' की धारा 5बी को उन्हीं कारखानोंक में लागू करने का प्रावधान रखा है जहां 1000 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। उल्लेखनीय है कि पहले यह प्रावधान हर उस कारखाने पर लागू था जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य
>
> (शेष पेज दस पर)

भ्रष्ट विलासियों के इस फर्जी लोकतंत्र को खारिज करो!

पेज एक से आगे

के बूते पर ही चल सकता है। यही वजह है कि सत्ता के दलाल पहले पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम किया करते थे पर आज तो अमरसिंह जैसे शुद्ध दलाल बाकायदा सामने आकर शान से काम कर रहे हैं और शीर्षस्थ मंत्रियों से लेकर उद्योगपतियों तक उनके दरवाजों पर लाइन लगाये रहते हैं।

इस भण्डाफोड़ ने तमाम विपक्षी दलों को जीवनदान दे दिया है। एक के बाद एक जनविरोधी ी निर्णयों में सरकार की हां में हां मिला रही तमाम चुनावी पार्टियों को सरकार पर हल्ला बोलने के लिए भ्रष्टाचार के रूप में एक मुद्दा मिल गया है। और वह इस तरह से चिल्ला रही हैं मानो वे सारे ईमानदारी के पुतले हैं। पिछले पचास साल में भ्रष्टाचार को कला के स्तर तक पहुंचा देने वाली भ्रष्टावतार कांग्रेस से लेकर लालू प्रसाद यादव और जयललिता तक लकड़ी की तलवारें भांजने में लगे हुए हैं। वे यह मानकर चल रहे हैं कि बोफोर्स तोप घोटाला, चेक पिस्तौल घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बैंक घोटाला, शेयर घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, धोती घोटाला, टीवी घोटाला जैसे अनगिनत घोटाले अदालतों की भूलभुलैया में उलझकर जनता की कमजोर याददाश्त से उतर चुके हैं और वह बेखौफ अपने को देश के ईमान का पहरेदार घोषित कर सकते हैं।

वैसे तो यह सारी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। इनमें कौन बड़ा चोर और लुटेरा है यह तय करने के लिए शायद कोई सरकारी कमीशन बैठाना पड़े। जनता को लूटने के लिए यह सारे लुटेरे, ठग, बटमार, डाकू एक हो जाते हैं लेकिन सत्ता के लिए यह आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। इसीलिए आज मौका मिलते ही सत्ता से बाहर रह गये तमाम चोर सत्ता की फिर से गंध पाकर उन्मत्त हो गये हैं और गद्दी पर बैठे चोरों को नीचे खींचकर उनकी जगह हथियाने के लिए जी-जान एक किये हुए हैं। चोरों, गिरहकटों और तस्करों में भी एक आपसी भाईचारा होता है। पर राजनीतिक चोट्टों की नस्ल आम चोरों से अलग होती है। उनकी जाति काफी हद तक जंगली कुत्तों के करीब होती है जो अपने ही घायल या कमजोर साथी को नोंच कर खा जाते हैं। जिस तरह मुनाफे की होड़ में लगे पूंजीपति एक-दूसरे को मौका पाते ही खा जाने की ताक में लगे रहते हैं, उसी प्रकार पूंजीवादी राजनेता भी अपनी चमड़ी बचाने के लिए दूसरे को बलि का बकरा बनाने में नहीं हिचकते।

सच यह है कि चोरों-भ्रष्टाचारियों से कोई भी पूंजीवादी चुनावी पार्टी मुक्त नहीं है और आम जनता भी इस बात को जानती है। मुख्तसर सी बात यह है कि पूंजीपतियों के लूटतंत्र के राजनीतिक मुलाजिम भला सदाचारी और नैतिक कैसे हो सकते हैं? और क्यों हों? भ्रष्टाचार का शोर मचने पर काफी पहले भ्रष्टाचार की अम्मा इन्दिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार केवल भारत में ही नहीं है, यह एक विश्वव्यापी परिघटना है। इटली, जापान, कोरिया, श्रीलंका से लेकर भारत तक भ्रष्टाचार का शोर तो हर जगह है, इन्दिरा गांधी ने सही ही कहा था।

उदारीकरण और भूमण्डलीकरण का दौर खुली पूंजीवादी लूट का दौर है। पूंजीवाद के सभी आदर्शों के आवरण उतर चुके हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार का घटाटोप इसी की एक तार्किक परिणति है। भ्रष्टाचार हमारे देश में भी कोई नई चीज नहीं है। नेहरूकाल से लेकर अब तक इसका एक लम्बा सिलसिला रहा है। जैसे-जैसे स्वाधीनता आन्दोलन से जन्मे आदर्श सामाजिक-राजनीतिक जीवन में समाप्त होते गये हैं, जैसे-जैसे पूंजीवादी लूट बढ़ती गयी है और पूंजीवादी व्यवस्था का संकट गहराता गया है, वैसे-वैसे समाजवाद का मुलम्मा उतरता गया है। और वैसे-वैसे ठहरे हुए सामाजिक-राजनीतिक जीवन की संडांध बढ़ती गयी है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार की घटनाओं और परिमाण में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है। खुली बाजार व्यवस्था के दौर में भ्रष्टाचार का खेल भी खुल कर खेला जा रहा है। आज की दुनिया में सदाचारी पूंजीवाद (वैसे तो पूंजीवाद कभी भी सदाचारी नहीं था) की कल्पना नहीं की जा सकती।

पूंजीवाद समाज श्रम की लूट की बुनियाद पर टिका है। सभी कानून-संविधान और नैतिकता के नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं और श्रम की लूट को कानूनी ठहराना ही इनका असली मकसद होता है। जैसे-जैसे मेहनत की यह लूट बढ़ती जाती है और ज्यादा से ज्यादा नग्न निरंकुश होती जाती है वैसे-वैसे सामाजिक राजनीतिक जीवन के पोर-पोर में अराजकता, अपराध और हर तरह के भ्रष्टाचार के विषाणु घुस जाते हैं।

हर तरह के घोटालों और भ्रष्टाचार से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है पूंजीवादी अर्थनीति और राजनीति का खात्मा। दूसरी और कोई भी राह नहीं है। भ्रष्टाचार मुख्य रोग नहीं है। यह तो रोग का लक्षण मात्र है। जरूरत है असली रोग के निदान की। जब तक साम्राज्यवादी और पूंजीवादी लूट का अस्तित्व रहेगा, जब तक पूंजीवादी उत्पादन और विनिमय प्रणाली रहेगी तब तक कमीशनखोरी और दलाली भी रहेगी और तबतक राजनीतिक भ्रष्टाचार भी रहेगा। आज सत्ता के मद में पागल शासक अपनी व्यवस्था को अजर-अमर मानने की वही भूल कर रहे हैं जो कूड़े के ढेर में जाने से पहले इतिहास में सभी शोषक वर्ग करते रहे हैं। जनता आज खामोश दिखती है पर इतिहास की दिशा पहचानने वाले जानते हैं कि सत के नीचे ज्वालामुखी सुलग रहा है। पौराणिक कथा है कि जघन्य, घिनौनी विलासिता में डूबे पाम्पेई शहर के धनिकों पर विसूवियस ज्वालामुखी का कहर फट पड़ा था। जनता को तबाही और दुखों के सागर में डुबोकर अपने महलों में रंगरेलियां में डूबे शासकों पर लोगों के गुस्से का ज्वालामुखी कब फट पड़े, कोई नहीं जानता। पाम्पेई के तो अवशेष सैलानियों के देखने के लिए बचे रह गये हैं लेकिन इन आदमखोरों के अवशेष भी ढूंढ़े नहीं मिलेंगे।

शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस (23 मार्च) के अवसर पर

भगतसिंह की जेल नोटबुक का एक पन्ना

(भगतसिंह की जेल नोटबुक का अध्ययन करने पर यह बात बेहिचक कही जा सकती है कि अमेरिकी समाजवादी यथार्थवादी लेखक जैक लंडन उनके प्रिय लेखकों में थे। मजदूर वर्ग और क्रान्ति के बारे में जैक लंडन के महान उपन्यास 'आयरन हील' को उन्होंने बेहद चाव के साथ और पूरे मनोयोग से पढ़ा था। विश्व सर्वहारा के महान शिक्षक और रूसी क्रान्ति के नेता लेनिन भी जैक लंडन के रचनाओं के जबर्दस्त प्रशंसक थे और उन्हें वह गहरी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। सचमुच यह कितना दिलचस्प संयोग है कि जैक लंडन मानवता को हर प्रकार के शोषक उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए सर्वहारा क्रान्ति को अपरिहार्य मानने वाले बीसवीं सदी के दो महान क्रान्तिकारी नेता लेनिन और भगतसिंह -- जो अलग-अलग देशों के थे और एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाये थे -- दोनों के प्रिय रचनाकार थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब लेनिन काफी अस्वस्थ थे तो उनकी पत्नी और साथी क्रुप्सकाया जैक लंडन की रचनाएं उन्हें पढ़कर सुनाती थी। ...और शहीदे आजम भगतसिंह फांसी की कालकोठरी में जैक लंडन को पढ़ रहे थे। सच है, जब सपने एक हों, लक्ष्य हो तो मानवीय भावनाएं भी एकरूप हो जाती हैं। और ऐसे में सरहदें, जो वर्गीय शोषण और वर्गीय स्वार्थों की उपज है, बेमानी हो जाती हैं।

यहां भगतसिंह की जेल नोटबुक में उद्धृत जैक लंडन की अमर रचना 'आयरन हील' का एक अंश हम प्रस्तुत कर रहे हैं। - सम्पादक

सत्ता ...।

एक समाजवादी नेता ने धनिकतंत्र की एक मीटिंग को सम्बोधित किया और उन पर समाज के कुप्रबन्ध का दोष लगाया और इस प्रकार पीड़ित मानवता के सम्मुख उपस्थित सभी विकरालताओं और दुख-तकलीफों की सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थोप दी। बाद में एक पूंजीपति (मि. विक्सन) उठ खड़ा हुआ और उसे इस प्रार सम्बोधित किया:

इस पर हमारा जवाब यह है। हमारे पास तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने के लिए शब्द नहीं हैं। जब तुम अपने गर्वीले मजबूत हाथ हमारे महलों और वैभव की ओर बढ़ाओगे, तब हम तुम्हें दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। बमगोलों की गड़गड़ाहट और मशीनगनों की तड़तड़ाहट से हम अपना जवाग देंगे। हम तुम क्रान्तिवादियों को अपनी एड़ियों तले पीस डालेंगे, और तुम्हारे चेहरों को कुचल डालेंगे। यह दुनिया हमारी है। हम इसके मालिक हैं और यह हमारी ही रहेगीं जहां तक श्रम की बात है, यह तो जबसे इतिहास शुरू हुआ तभी से धूल चाटता रहंगा जब तक श्रम की बात है, यह तो जब से इतिहास शुरू हुआ तभी से धूल चाटता रहो है, और मैंने इतिहास को ठीक से पढ़ा है। और यह तब तक धूल चाटता रहेगा जब तक हमारे और हमारे उत्तराधिकारियों के हाथ में सत्ता रहेगी।

"एक शब्द है – सत्ता। यह सभी शब्दों का राजा है। ईश्वर नहीं, धन-वैभव नहीं, बल्कि सत्ता। अपनी जबान पर रख लो और तब तक रखे रहो जब तक कि यह उसे झनझनाने न लगे।"

"मुझे उत्तर मिल गया", अर्नेस्ट (उस समाजवादी नेता)[1] ने निर्विकार भाव से कहा। "एकमात्र यही उत्तर दिया भी जा सकता था। सत्ता हम मजदूर वर्ग के लोग इसी का तो प्रचार करते हैं। हम जानते हैं और अपने कटु अनुभव से भलीभांति जानते हैं, कि सत्य की, न्याय की, मानवता की, कोई भी अपील कभी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे दिल भी तुम्हारी उन एड़ियों की तरह ही कठोर हैं जिनसे तुम ग़रीबों के चेहरे कुचलते हो। इसीलिए तो हमने सत्ता का प्रचार किया है। लेकिन, चुनाव के दिन हमारे मतपत्रों की ताकत तुमसे तुम्हारी सरकार छीन ले जायेगी ...।"

"मान लो यदि चुनाव में तुम्हारी जीत के बावजूद हम तुम्हें सत्ता सौंपने से इंकार कर दें तो?"

"हमने उस पर भी सोच रखा है", अर्नेस्ट ने जवाब दिया। "और इसका जवाब हम तुम्हें गोलियों से देंगे। सत्ता, तुम्हीं ने इसे शब्दों का राजा कहा है। बहुत अच्छा! सत्ता, देखेंगे इसे। और जिस दिन हम चुनाव में विजय हासिल कर लेंगे, और तुम हमारी इस संवैधानिक और शान्तिपूर्ण ढंग से हासिल की गयी सत्ता को हमें सौंपने से इंकार कर दोगे, तो तुम्हारे इस सवाल के जवाब में कि हम क्या करेंगे – उस दिन, मैं बता दूं, कि हम तुम्हें इसका जवाब देंगे, हम बमगोलों की गड़गड़ाहट और मशीनगनों की तड़तड़ाहट से अपना जवाब देंगे।

"तुम हमसे बच नहीं सकते। यह सही है कि तुमने इतिहास को ठीक से पढ़ा है। यह सही है कि श्रम इतिहास के आरम्भ से ही धूल चाटता आ रहा है। और यह भी सही है कि जब तक तुम्हारे और तुम्हारे उत्तराधिकारियों के हाथ में सत्ता रहेगी, तब तक श्रम धूल ही चाटता रहेगा। मैं तुमसे सहमत हूं। सत्ता ही निर्णायक होगी, जैसा कि हमेशा होता आया है; यही तो वर्गों का संघर्ष है। जैसे तुम्हारे वर्ग ने पुराने सामन्ती तंत्र को ध्वस्त किया, ठीक वैसे ही मेरा वर्ग, मज़दूर वर्ग, तुम्हारे वर्ग को ध्वस्त कर डालेगा। अगर तुम अपने प्राणिविज्ञान और अपने समाज विज्ञान को भी उतनी ही स्पष्टता से पढ़ो, जितनी स्पष्टता से तुम इतिहास पढ़ते हो, तो तुम देखोगे कि मैंने जिस हश्र का वर्णन किया है वह अपरिहार्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें एक वर्ष लगेगा, दस वर्ष लगेंगे या हजार वर्ष लगेंगे – यह तय है कि तुम्हारा वर्ग मिट्टी में मिल जायेगा। और यह सत्ता के जरिये ही होगा। हम मेहनतकश इस शब्द को इतना रट चुके हैं कि हमारे दिमाग इससे झनझना रहे हैं। सत्ता। यह एक राजोचित शब्द है।"

– जैक लण्डन कृत आयरन हील (पृ. 88)

यह हादसा नहीं है

गाजियाबाद, 6 मार्च (बिगुल संवाददाता)। असुरक्षित और ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिये मजबूर मज़दूर आये दिन दुर्घटनाओं के शिकार होकर असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही एक दुर्घटना साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 'भूषण स्टील एण्ड ट्यिस लिमिटेड' में घटी, जहां चार मज़दूरों ने दम तोड़ दिया और दर्जन भर मज़दूर गंभीर रूप से घायल हैं।

अभी हाल ही में लगे भूषण स्टील की इस नयी इकाई में लोहा गलाने का काम चल रहा था कि अचानक एक विस्फोट के बाद भट्टी से गले लोहे का लावा निकलने लगा और वहां काम कर रहे दर्जनों श्रमिकों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब दस-पंद्रह फुट तक ऊपर उठने वाले इस लावे की गिरफ्त में आये कुछ मज़दूर तो पूरी तरह झुलस गये थे। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गयी। देखते-देखते, पूरा इलाका चीख-पुकार के करुण दृश्य में बदल गया। अंबिका यादव, नरेश यादव, बाबूलाल और राजकिशोर की तो अस्पताल जाते-जाते ही मौत हो गयी, कई की हालत अभी गम्भीर बनी हुई है। उधर पुलिस ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए महज वर्क्स और मेंटेनेंस के दो प्रबन्धकों को हिरासत में ले लिया है। कारखाना मालिक को बचाने का प्रयास करते हुए पुलिस यह तर्क दे रही है कि लिमिटेड कम्पनी का कोई एक मालिक नहीं होता।

दरअसल इन तमाम कारखानों में मज़दूरों की सुरक्षा के न तो कोई प्रावधान हैं और न ही आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। इस कारखाने में भी भट्टी का तापमान 1600 डिग्री सेंटीग्रेट था जहां काम करने वाले श्रमिकों के पास कपड़े, दस्ताने, हेलमेट आदि फायरप्रूफ भी नहीं है और न ही आग बुझाने के यंत्र हैं। प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा भी नहीं है। मज़दूर आये दिन छोटी-मोटी दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं, जिनकी कोई पूछताछ नहीं होती है।

वैसे भी ठेकेदारी में काम करने वाले मज़दूरों की ज़िन्दगी ये मुनाफाखोर कारखानेदार कीड़े-मकोड़ों से अधिक नहीं समझते हैं। यह स्थिति महज भूषण स्टील की ही नहीं है बल्कि ज्यादातर कारखानों की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और लगातार बदतर होती जा रही हैं।

यह सौदा महंगा पड़ेगा

पेज नौ से आगे

में सीधे सरकारी खर्च को इस बार और कम कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के मद में इस बाद पिछले साल की तुलना में 386.03 करोड़ रुपये कम दिये गये हैं। इसकी जगह छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कर्जे देने की घोषणा की गयी है। देश में अध्ययन के लिए 7.5 लाख और विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये कर्ज के रूप में देने का ऐलान है। इस कर्जे को 5-7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा। कर्जे का यह इंतजाम किस तबके के छात्रों के लिए किया जा रहा है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं।

बजट में तफसील की ढेरों ऐसी बातें हैं, जिनके आधार पर यह साफ जाहिर है कि यशवन्त सिन्हा ने इसे नया सौदे में किसको फायदा पहुंचाने का पक्का इन्तजाम किया है। जाहिर है, जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने का जिम्मा उन पर है, उसकी मजबूरियों में ही उन्होंने यह कदम उठाये हैं। उनके इस सौदे से यह संकट दूर होगा या नहीं, उनकी क्या-क्या मजबूरियां है। इस पर चिन्तित होने के लिए मेहनतकशों के पास न समय है न वे इस हालत में हैं कि अर्थशास्त्र के बारीक हिसाब-किताब लगायें। उनके लिए यही समझना काफी है कि यह सौदागिरी उनकी जिन्दगी पर मुसीबतों के नये-नये पहाड़ बनकर टूट रही है। और मुसीबतें बर्दाश्त करने की आखिरी हदें कभी न कभी आती हीं हैं। यशवन्त सिन्हा उसी ओर ध कियाते जा रहे हैं। लेकिन! वजीरे खजाना! आपको शायद इलहाम तक न हो, यह नया सौदा काफी महंगा साबित होने वाला है।

श्रम क़ानूनों में ख़तरनाक बदलाव

पेज नौ से आगे

करते रहे हैं। वर्तमान समय में देश में 85 प्रतिशत से ज्यादा कारखाने ऐसे हैं जहां नियमित श्रमिकों की संख्या 1000 से कम है। किश्तों में इस परिवर्तन में भी सरकार की एक साजिश है। इससे 1000 से कम और ज्यादा वाले कारखाना मज़दूरों को आपस में बांटकर मज़दूरों की ताकत भी कमजोर करना चाहती है। वैसे आने वाले नये श्रम क़ानून में इस पूरी धारा को ही ख़त्म करने का प्रावधान हे।

इस संशोधन का सीधा मतलब है कि किसी भी कारखानेदार को श्रमिकों की छंटनी अथवा कारखाने की तालाबन्दी के लिये सरकार से पूर्व अनुमति की औपचारिकता भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब बजट प्रस्ताव पास होने के बाद 1000 से कम श्रमिकों वाले कारखाने का प्रबन्धतन्त्र जब चाहे जिस कर्मचारी को बाहर खदेड़ सकता है और निकाले गये लोगों के पास शिकायत करने का कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा।

इसके साथ ही वित्त मन्त्री ने 'अनुबन्ध श्रम क़ानून' में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन से कम्पनियों को अनुबंध (ठेके) पर श्रमिकों को रखने और उन्हें नौकरी से निकालने की भी खुली छूट मिल जायेगी। 1970 में लागू 'अनुबन्ध श्रम क़ानून' के तहत निश्चित सीमा से अधिक समय तक कार्य कर चुके ठेका श्रमिकों को नियमितिकरण का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा नियमित श्रेणी में न आने वाले स्थानों पर ही ठेका प्रणाली लागू थी।

यूं तो पहले भी ठेका मज़दूरों की स्थिति दयनीय थी और श्रम क़ानूनों का खुला उल्लंघन होता रहा है। लेकिन इस नये परिवर्तन से प्रबन्धकों को क़ानूनी अधिकार मिल जायेगा। अब स्थायी किस्म के कामों पर भी ठेका प्रणाली का रास्ता खुल जायेगा। इसके अलावा बड़ी कम्पनियों के लिये काम करने वाली सहायक छोटी कम्पनियां (इन्सेलरी) में भी पूर्णत: ठेका प्रणाली लागू हो जायेगी। वित्त मन्त्री ने औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने की दुहाई देते हुए यह भी ऐलान किया कि संसद के इसी सत्र में श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद क़ानून और ठेका श्रमिक क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया जायेगा। वित्त मन्त्री ने इन ख़तरनाक प्रावधानों के बीच श्रमिकों को एक लालीपॉप थमाने की भी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि छंटनीशुदा व्यक्ति को कुल नौकरी की अवधि का पंद्रह दिन की जगह 45 दिन प्रतिवर्ष की दर से भुगतान किया जायेगा। नौकरी खोने वाले व्यक्ति के लिये आश्रय बीमा योजना भी शुरू करने का एलान किया गया।

भविष्य के मद्देनजर घोषित इन "राहत" योजनाओं का "लाभ" पाने के काबिल कितने श्रमिक होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पहली बात तो यह कि जब सब कुछ ठेकेदारी के मातहत होगा तो फिर मुआवजा कैसा? दूसरे, नियमित श्रमिकों की संख्या और कार्यावधि ही इतनी सीमित होगी कि इसका 'लाभ' भी मालिकों को ही मिलेगा।

श्रम क़ानूनों में वर्तमान परिवर्तन से कारखाना मालिक अमेरिकी मुहावरे 'हायर एण्ड फायर' (जब चाहो काम पर रखो, जब चाहो निकाल बाहर करो) की तर्ज पर मज़दूरों की अपनी मर्जी का गुलाम बना लेंगे । मज़दूरों के रोजगार सुरक्षा का रहा-सहा क़ानूनी हथियार पूरी तरह छिन गया है। कारखानेदार अपनी सुविधा के अनुसार मज़दूरों को 'हायर' करेंगे (काम पर रखेंगे) और "ज़रूरत" ख़त्म हो जाने पर 'फायर' (निकाल बाहर) कर देंगे। न सरकार से मंजूरी लेने का झंझट, न अदालतों का पचड़ा।

वैसे, पूरे श्रम क़ानून में बदलाव का जो दस्तावेज अब आने वाला है उसमें ट्रेड यूनियन ऐक्ट में जो संशोधन सुझाये गये हैं उससे यूनियनें मज़दूरों के हितों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं न होकर कारखाना मालिकों की एजेंसी बनकर रह जायेंगी। अब यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम सात सदस्यों की जगह दस प्रतिशत मज़दूरों की भागीदारी को अनिवार्य बनाया जा रहा है। यही नहीं, यूनियन में "बाहरी" व्यक्तियों के प्रवेश पर भी अंकुश लगाने की योजना है। श्रमिक विवादों को हल करने के लिए अब तक चली आ रही त्रिपक्षीय वार्ता की परिपाटी (सरकार की अध्यक्षता में श्रमिक और प्रबन्ध तन्त्र के बीच वार्ताओं की परिपाटी) से सरकार अपना हाथ खींच रही है। "श्रमिक गतिशीलता" बढ़ाने के नाम पर यह परिवर्तन भी श्रमिकों को प्रबन्ध तन्त्र का गुलाम बनाकर रख देगा। "उत्पादकता बढ़ाने" की धुन में मशगूल मुनाफाखोरों को अब यह क़ानूनी अधिकार मिल गया है कि वे "अनुशासनहीनता" और "असंतोषजनक" काम के आधार पर किसी की भी छुट्टी कर सकते हैं। उनका सीधा फार्मूला है कि मज़दूर बिना चूं-चपड़ किये अपने खून के एक-एक कतरे को सिक्कों में बदलकर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरते रहें।

8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मर्यादपुर में आयोजित सभा –

दोहरे शोषण की मार झेल रही नारी की आज़ादी मेहनतकशों के मुक्ति-संघर्ष से जुड़ कर ही सम्भव है!

• बिगुल संवाददाता

मर्यादपुर, मऊ, मार्च 2001

"भूमण्डलीकरण के इस दौर में नारी दोहरे शोषण की मार झेल रही है। एक तरफ वह बाज़ार व्यवस्था द्वारा पैदा की जा रही मंहगाई, बेरोजगारी व मेहनतक़श जनता की तबाही-बर्बादी का सीधा सामना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था द्वारा पैदा की जा रही नारी विरोधी मानसिकता को भोग रही है। औरतों को आज इसके खिलाफ संगठित होना होगा और मज़दूरों-किसानों के साथ मिलकर, आम मेहनतक़श जनता को तबाह करने वाली व्यवस्था और उसकी पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करना होगा।" यह बात 'नारी सभा' गोरखपुर इकाई की संयोजिका मीनाक्षी ने कही।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर नारी सभा मर्यादपुर द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, आज पूरी दुनिया के पैमाने पर औरत का श्रम सबसे सस्ता है, उसके सस्ते श्रम का देशी-विदेशी कम्पनियां शोषण कर रही हैं। औरत का श्रम आज पूरी दुनिया के पूंजीपतियों की थैली भरने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। वहीं इस बाजारू व्यवस्था ने औरत के शरीर को उपभोकता माल में तब्दील कर दिया है, उसने नारी देह को प्रचार का माध्यम बना दिया है। इसके विरुद्ध संगठित व्यवस्था विरोधी आन्दोलन खड़ा करना होगा, तभी जाकर नारी मुक्ति संभव है।

महिला दिवस के अवसर पर मर्यादपुर में आयोजित सभा

नारी सभा मर्यादपुर इकाई की संयोजिका रजुली देवी ने कहा कि, आज से सवा सौ साल पहले अमेरिका के शिकागो शहर की कामगार स्त्रियों द्वारा, बराबरी और आज़ादी के लिए दी गई शहादत हम सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। औरतों की बराबरी की लड़ाई आज भी जारी है। समानता और स्वतंत्रता के लिए संगठित संघर्ष की तैयारी करना ही आज शिकागो की शहीद शेरनी स्त्रियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभा में बोलते हुए आशा ने कहा कि, हमारे देश में भी नारी आन्दोलन का लम्बा और गौरवशाली इतिहास रहा है। स्त्रियों ने मेहनतक़श वर्ग के क्रांतिकारी आन्दोलन में कन्ध से कन्धा मिलाकर संघर्ष किया है। स्त्री को जो थोड़ी-बहुत आज़ादी का अवसर मिला है वह उसी का परिणाम है। लेकिन आज भी अधिकांश स्त्रियां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हैं। उसकी जीवन दिशा आज भी पुरुष समाज की ज़रूरतों से तय होता है। इस हालत को बदलने के लिए हमें लड़ना होगा और साथ ही हमारे भाईयों, पिता, चाचा, काका व बाबा को हमारा साथ देना होगा इसी में उनका भी सम्मान है।

नारी सभा की सांस्कृतिक टोली की निर्मला ने कहा कि, 'आज भी गांव की कामगार स्त्रियों की दशा बदतर है। परिवार चलाने के लिए उसे जीवन की कठिनतम हालातों में जीना पड़ता है।'

बच्चों को लेकर बकरी, गाय, भैंस, बैल पालने तक – खाना पकाने के लिए 7-7 मील चलकर लकड़ी जुटाने से लेकर खेतों तक उसे खटना पड़ता है। दहेज की आग में उसे ही जलना पड़ता है। निश्चित ही इस हालात को बदलना होगा और यह संगठन व एकता से ही संभव है।

इसके अलावा सभा को बिगुल मजदूर दस्ता के आदेश कुमार ने सम्बोधित किया। सांस्कृतिक टोली में निर्मला, शिक्षा, लालू, सोना, किशोरी, इन्द्रदेव व रामप्रीत थे। सभा में बड़ी संख्या में स्त्री-पुरुष शामिल थे। सभा का संचालन नारी सभा, गोरखपुर इकाई की शालिनी ने किया।

आयोजन की शुरुआत में नारे लगाता हुआ महिलाओं का जुलूस मर्यापुर से अजोरपुर, इतिराई, बांकेपुर, लखनौर व अन्य गांवों से होता हुआ वापस मर्यादपुर बस स्टैण्ड के पास बाग में पहुंचकर सभा में नारी सभी की ओर से क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये गये व सभा के अंत में नारी सभा व देहाती मज़दूर किसान यूनियन की सांस्कृतिक टोली ने क्रान्तिकारी बिरहा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

उ.प्र. में न्याय और महंगा बिकेगा

(बिगुल संवाददाता)

लखनऊ। मुनाफाखोरों की चाकर भाजपा सरकार व्यापक ग़रीब आबादी को शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने के साथ ही न्याय पाने के अधिकार को भी अब अमीरज़ादों की बपौती बना रही है। अपने ताजा फैसले में उत्तर प्रदेश, सरकार ने अदालती (कोर्ट) फीस में एकमुश्त दस गुने की भारी वृद्धि कर दी है।

सरकार का यह तर्क है कि राज्य में इस समय तक लागू कोर्ट फीस बेहद कम है और सरकार को स्टैम्प ड्यूटी से महज 30 करोड़ रुपये की आय होती है जबकि अदालतों के संचालन में क़रीब 270 करोड़ रुपये व्यय होता है। अब नयी दरों के लागू होने के बाद उसे 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी कम होने के कारण भूमि सम्बन्धी मामूली विवादों के लिये हर आदमी अदालत में दावा ठोंक देता है। अब ऐसी प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी।

क्या खूब तर्क दिया है सरकार ने! पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का हक है और यह सुविधा उसे निशुल्क मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूंजीवादी निजाम में हर चीज की भांति न्याय भी पैसे वालों को ही मिलता है। अब यह पूरी तरह से पैसे वालों की ज़ागीर बन जायेगी। दूसरे न्यायालय के बम्पर खर्च की जिम्मेदार आम ग़रीब जनता नहीं है। न्यायालयों के भारी-भरकम लवाज़मात के बावजूद विवादों के लम्बे समय तक निपटारा न होने से जहां आम जनता परेशान होती रहती है वहीं इस लवाज़मात पर होने वाला खर्च भी बढ़ता जाता है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग़रीब आबादी भूस्वामियों-धन्नासेठों की अंधेरगर्दी के खिलाफ कुछ न्याय की उम्मीद रखती रही है, अब इस महंगे कोर्ट फीस की वजह से इससे वंचित हो जायेगी। इससे पैसे वालों की तो चांदी हो जायेगी, जबकि ग़रीब आबादी की परेशानियां और बढ़ जायेंगी।

इस पूंजीवादी निजाम में व्यापक आम जनता को न्याय की उम्मीद पालना ही बेमानी होगा। यह समाज तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की तर्ज पर चलता है। न्याय तो उसके अपने राज – समतामूलक समाज में ही मिल सकता है। उसे मुनाफाखोरों से उम्मीद पालने की जगह अपने वास्तविक राज की स्थापना के कठिन कामों में ही लगना पड़ेगा।

मज़दूर औरतों पर झपटते वहशी भेड़िये

(बिगुल प्रतिनिधि)

लुधियाना। उजरती गुलामों (मज़दूरों) के इस महासागर (लुधियाना) में लाखों मज़दूर दिन-रात आर्थिक शोषण के साथ-साथ मालिकों और उनके गुण्डों द्वारा पिटाई एवं गाली-गलौज़ झेलते हैं। वहीं मज़दूर औरतों को आर्थिक शोषण के साथ-साथ शारीरिक शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। फैक्टरी मालिक और उनके गुण्डे अक्सर मज़दूर औरतों को अपनी जानवरी हवस का शिकार बनाने के लिए घात लगाये रहते हैं। ऐसी ही एक घटना गत दिनों लुधियाना में घटी।

इस शहर के दशमेश नगर मुहल्ले में गली नं. 12/7 में पूनम प्रोडक्ट्स नामक एक छोटा सा कारखाना है। इसमें काम करने वाली एक मज़दूर औरत गत 14 फरवरी की रात को फैक्टरी का काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। फैक्टरी के सामने अपने एक दोस्त कुक्कू की दुकान पर बैठे फैक्टरी मालिक अरुण कुमार ने उस औरत को दुकान पर बुलाया और दोनों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मगर उस गैरतमन्द मेहनतक़श औरत ने उन गुण्डों का डटकर मुकाबला किया। दुकान पर शोर सुनकर वहां लोग इकट्ठा होने लगे और उस औरत को गुण्डों के चंगुल से आज़ाद करवाया गया।

बाद में कुछ जनसंगठनों के दबाव में इन गुंडों ने अपनी इस कमीनी हरकत के लिए मुहल्ले के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और तीन हजार रुपये जुर्माना भरा।

पूनम प्रोडक्ट्स में औरत मज़दूरों सहित कुल 30-35 मज़दूर काम करते हैं। फैक्टरी मालिक सिर्फ 12-13 सौ रुपये तनख्वाह पर मज़दूरों से 12-12 घंटे काम लेते हैं। औरत मज़दूरों की तनख्वाह और भी कम है। मज़दूरों से सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक काम लिया जाता है। औरतों से जानबूझकर देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे ये आदमजाद भेड़िये उनका शिकार कर सकें।

14 फरवरी वाली घटना कोई अकेली घटना नहीं है। लुधियाना के तमाम औद्यागिक इलाकों में इस तर की घटनाएं लगभग रोज होती रहती हैं। कुछ लोगों के सामने आ जाती हैं, कुछ दबा दी जाती हैं। पूनम प्रोडक्ट्स जैसे तमाम कारखाने हैं जिनके मालिकान मज़दूरों के किसी ताकतवर संगठन के न होने का फ़ायदा उठाकर मनमाना अत्याचार करते रहते हैं। स्थानीय पुलिस-प्रशासन से भी इनकी मिलीभगत रहती है, जिससे ये बेखौफ होकर अपनी मनमर्जी करते रहते हैं।

फैक्टरी मालिकों के जोरो-जुल्म और शोषण के खिलाफ मज़दूरों के दिलों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ है जो कभी-कभार फूटता भी रहता है और कभी-कभार किसी इक्का-दुक्का मसले पर वे एकजुट होकर आवाज भी उठाते हैं। लेकिन, यह बेहद नाकाफी है। जब तक समूचे औद्योगिक इलाके में मज़दूरों का एक जुझारू क्रान्तिकारी संगठन नहीं बनेगा, तब तक मालिकान और उनके गुण्डों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिखराव हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस क्षेत्र के सचेत, समझदार मजदूर साथियों को हिम्मत के साथ पुराने तजुर्बों से सीखते हुए इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना ही होगा क्योंकि आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं।

ईमानदार पड़ताल ज़रूरी

पेज तीन से आगे

कम्युनिस्ट आत्मालोचनात्मक पहुंच और पद्धति नहीं मौजूद है तो दूसरे संगठनों से स्वस्थ संवाद-राजनीतिक वाद-विवाद हो सके, इसकी उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि जब जनवादी केन्द्रीयता की सप्राण आवयविक व्यवस्था के अभाव में अधिकांश संगठन एक निष्प्राण निकाय बने हुए हैं तो क्या ऐसे दो निष्प्राण निकाय आपस में अन्तर्क्रिया कर सकते हैं? यदि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन की एकजुटता की प्रक्रिया आगे बढ़नी है तो सांगठनिक लाइन के इस सवाल की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह अपने आप में एक विचारधारात्मक महत्व का सवाल है और विचारधारात्मक-राजनीतिक लाइन पर पहले से मौजूद मतभेदों से कम महत्व का सवाल नहीं है। यह कम्युनिस्ट संगठन के बोल्शेविक उसूलों से जुड़ा सवाल है। इसलिए, इस सवाल का हल होना भी ज़रूरी है।

मतभेदों के हल होने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, ठहराव कैसे टूटेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इस बारे में दृढ़ निश्चय के साथ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन साथी सियाशरण शर्मा के सुझाव महत्वपूर्ण हैं। किसी साझा विचारधारात्मक मंच का निर्माण एक ज़रूरी कदम होगा। यह मंच कोई साझा पत्रिका भी बन सकती है। इस दिशा में एकाध प्रयास हुए हैं जो अभी बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं, लेकिन अगर यह आगे बढ़ सकें तो यह मौजूदा गतिरोध को तोड़ने की दिशा में मददगार हो सकता है। साथ ही, जनता से जुड़े साझा मुद्दों पर कोई व्यापक मंच भी यदि बन सके तो यह भी बेहद मददगार होगा। कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संगठनों को इस बारे में ही पहलकदमी लेनी चाहिए।

अन्त में, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन के टूट-फूट-बिखराव के कारणों पर अपनी राय रखते समय सिर्फ एक प्रमुख बुनियादी कारण की चर्चा की है। जाहिर है, अन्य अनेक वस्तुगत-मनोगत कारणों और इतिहास में निहित अनेक कारण हैं जिनकी जटिल और संश्लिष्ट संघात से मौजूदा स्थिति पैदा हुई है। इनमें से कुछ कारणों की साथी अनादिचरण ने अपनी टिप्पणियों में बेहद सारगर्भित चर्चा की थी। बहस आगे बढ़ती है तो उन पर विस्तृत चर्चा का अवसर मिलेगा। फिलहाल, इतना ही।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

ललित सती, दिल्ली

खेती को सबसिडी या पूंजीपतियों की चांदी?

सरकार की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके दस वर्षों में 50 अरब रुपये हड़पे खाद कारखानों ने

(विशेष संवाददाता)

दिल्ली। किसानों को सस्ता उर्वरक देने के लिए सरकार उर्वरक कारखानों को जो सबसिडी (प्रतिधारण मूल्य) देती रही है, उनमें घपला करके इन कारखानों के मालिक पूंजीपतियों ने पिछले दस वर्षों के दौरान सरकारी खजाने से 5,000 करोड़ (50 अरब) रुपये डकार लिये हैं। मुनाफे की हवस में पगलाये हरामखोरों को मेहनतकशों के श्रम की "कानूनी लूट" मात्र से तसल्ली नहीं होती है और वे हर तरह की धोखाधड़ी को कोई अवसर नहीं चूकते। कोई भी पूंजीवादी सरकार वास्तव में इन्हीं पूंजीपतियों की 'मैनेजिंग कमेटी' होती है, जो पूंजीवादी शोषण के साथ ही हर तरह की लूट और धोखाधड़ी के फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने का और उसमें हर तरह से मदद करने का ही काम करती है। उर्वरक कारखानों के मालिकान की धोखाधड़ी-जालसाजी के इस ताजे पर्दाफाश ने भी इसी सच्चाई को एक बार फिर उजागर किया है। अब चूंकि अखबार भी इन्हीं पूंजीपतियों के हैं, इसीलिए हमेशा ही व्यापक मेहनतकश आबादी तक ऐसी खबरें पहुंचने से रह जाती हैं।

इस फर्जीवाड़े का इतिहास लगभग दस साल पुराना है। 1991 से यह लूट जारी है। तबसे, कांग्रेस, तीसरे मोर्चे के घटक पूंजीवादी दल, और नकली वामपंथियों से लेकर भाजपा तक – सभी सत्ता में रह चुके हैं और इस सच्चाई से न सिर्फ इन सभी दलों के टुकड़खोर सांसद परिचित हैं, बल्कि सरकार में रहते हुए इन सभी दलों ने इस लूट में मदद पहुंचाई। और अब जब यह अरबों की लूट छिप नहीं पा रही है तो भाजपा सरकार इस कोशिश में लगी है कि पूंजीपतियों को फर्जी दावे के आधार पर वसूली गई रकम वापस न करनी पड़े। विपक्षी सांसद भी इतने बड़े मसले को सार्वजनिक बनाने से बच रहे हैं और मामले को अन्दरखाने निपटा लेना चाहते हैं।

पाठकों की जानकारी के लिए यह साफ कर देना ज़रूरी है कि प्रतिधारण मूल्य की यह योजना 1977 से लागू है जिसके तहत उर्वरक कारखानों को लागत पर 12 फीसदी का मुनाफा दिया जाता है। इसी को सबसिडी कहा जाता है। देश में हर साल दो करोड़ टन यूरिया बनता है जिसका एक चौथाई उत्पादन नाफ्था और फर्नेस ऑयल से होता है। उत्पादन की लागत का निर्धारण भारत सरकार के बड़े अफसरों की एक टोली करती है। ये अफसर पूंजीपतियों की फेंकी बोटियां चूसकर हमेशा से लागत अधिक दिखाते रहे हैं ताकि पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा सबसिडी हासिल कर सकें। इस तरह से 1990 तक कितनी कमाई पूंजीपतियों ने की, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है।

अब पिछले दस सालों में जो हुआ है, वह तो खुलेआम डाकेज़नी है। हुआ यह है कि लागत-निर्धारण का जो पैमाना 1991 में संशोधित कर दिया जाना चाहिए था वह आज तक नहीं हुआ है। कारखाने कम लागत पर उर्वरक बना रहे हैं और ज्यादा रकम सरकारी खजाने से हड़प रहे हैं। स्वयं कारखानों ने जो आंकड़े सरकार को दिये हैं, उन्हीं से यह जालसाज़ी साफ हो जाती है। लेकिन सरकार न सिर्फ इस पूरे मामले को दाबे हुए है, बल्कि यशवंत सिन्हा ने अब अपने बजट भाषण में यह घोषणा कर दी है कि प्रतिधारण मूल्य स्कीम धीरे-धीरे समाप्त कर दी जायेगी। उनकी इस घोषणा से उन पूंजीपतियों को राहत मिली है जो वसूली से बचने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। ज्ञातव्य है कि हर उर्वरक कारखाने के साथ सरकार का यह करारनामा है कि सरकार से लिया गया फालतू पैसा वापस कर दिया जायेगा

यह मामला 'लीक' भी इसीलिए हुआ है कि मुनाफे के लिए गलाकाटू प्रतियोगिता में लगे पूंजीपतियों की दूसरी लाबियों से खाद कारखाना मालिकों की चांदी कटते नहीं देखी गई। फलतः सांसदों की अपनी लाबी से उन्होंने इस मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। लेकिन ग़ौरतलब बात है कि यह पूरा मामला जनता की नज़रों में न आ जाये, इसके लिए इस मामले को संसद में उठाने या मुद्दा बनाने की जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री को और एफ.आई.सी.सी. नामक उस कमेटी को बजट बनते समय ही एक पत्र भेजा, जिसकी जानकारी में यह घोटाला हुआ है। तुर्रा यह कि सांसदों-अफसरों की एक दूसरी लाबी उर्वरक कारखाना नालिकों के लिए काम कर रही है जिसमें सत्तारुढ़ और विपक्ष – दोनों ही तरफ के सांसद हैं। इनमें समाजवादी पार्टी से जुड़े कुख्यात सत्ता-दलाल अमरसिंह अग्रणी हैं। इस धर्मसंकट से वित्तमंत्री को उबारा उनकी आर्थिक नीति-ने। उन्होंने सबसिडी ही धीरे-धीरे (सन 2006 तक) खतम करने की घोषणा कर दी। यानी सरकारी खजाने से जनता की सम्पत्ति लूटने के बजाय अब पूंजीपति सीधे बाज़ार में मनमाने मूल्य पर खाद बेंचकर किसानों को लूटेंगे। अबतक लूटी गई रकम की वसूली की पूरी बात सरकार एकदम गोल कर गई, और इसपर संसद में विपक्ष की बेंचों से भी, एक कुत्ता तक नहीं भौंका।

इस लूट का अंदाज़ा सिर्फ कुछ तथ्यों से ही लगाया जा सकता है। खाद कारख़ाना मालिकों ने पिछले दस वर्षों के भीतर छः गुने से अधिक मुनाफा कमाया है जो लगभग 50 अरब रुपये की रकम है। सरकारी खजाने को हर रोज लगभग तीन करोड़ रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इन धोखेबाज़ पूंजीपतियों में डंकन (कानपुर) के मालिक जी.पी. गोयनका (159 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली), एम.सी.एफ. (मंगलौर) के मालिक विजय मलाया (43 करोड़ रुपये), एस.एफ.सी. (कोटा) के मालिक अजय श्रीराम (123 करोड रुपये), स्पिक (तूतीकोरन) के मालिक ए.सी. मुथैया (145 करोड़ रुपये), जुवारी (गोवा) के मालिक के.के. बिड़ला (75 करोड़ रुपये) सबसे आगे हैं। 11 कारखाने भारत सरकार के प्रबंधन में हैं और उनके प्रबंधन में बैठे नौकरशाह भी इस लूट में पीछे नहीं है। कुल 1138 करोड़ रुपये किसानों की मदद के बहाने इन्होंने सरकारी खजाने से हड़पे हैं। ग़ौरतलब है कि सरकार ने अभी भी उर्वरक उत्पादन में लागत-निर्धारण के पैमाने में संशोधन की घोषणा नहीं की है। यानी अप्रैल 2006 में यूरिया को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने के चरणबद्ध कार्यक्रम के जारी रहने तक पूंजीपतियों को सरकारी खजाने से जालसाजी करके रकम हड़पते रहने की छूट जारी रहेगी। हां, उसकी रकम कम होती जायेगी और उनकी यह छूट बढ़ती जायेगी कि वे उत्पादन करने वाले मज़दूरों को ज्यादा से ज्यादा निचोड़कर और खुले बाज़ार में किसानों को ज्यादा से ज्यादा लूटकर अपनी तिजोरी भरें।

ग़रीबी की चिन्ता से दुबले भए प्रधानमंत्री जी!

मुकुल

आजकल माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के ग़रीबी की चिन्ता से काफी दुबले हुए जा रहे हैं। उन्होंने देश के सबसे विपन्न तबके (ग़रीबी रेखा से नीचे की आबादी) के लिये अन्त्योदय योजना घोषित की है। अभी-अभी उन्होंने देश के शीर्ष पूंजीपति घराने (टाटा ऊर्जा शोध संस्थान) द्वारा आयोजित पहले समेकित विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए फरमाया है कि विश्व भर में असमान विकास की खाई को पाटने के लिए विकसित देशों के बीच पूंजी के प्रवाह पर अन्तर्राष्ट्रीय शुल्क लगाकर वैश्विक ग़रीबी उन्मूलन कोष बनाया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल विदेशी ऋणों के भुगतान, ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग़रीबों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने में हो।

प्रधानमंत्री जी सम्मेलन में, देश-दुनिया में, अमीरी-ग़रीबी की बढ़ती खाई से भी खासा चिंतित दिखाई दिये। विश्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि दुनिया की आबादी का छठां हिस्सा 70 डालर (2800 रुपये) प्रतिदिन कमा रहा है जबकि साठ फीसदी लोगों को दो डालर (80 रुपये) रोजाना भी मुश्किल से मिल पाता है। (हालांकि यह आंकड़ा भी सच्चाई से काफी दूर है)।

यही नहीं, बाजपेयी की अगुवाई वाले 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन' (राजग) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी यह चिन्ता जाहिर की थी। उसमें लिखा है कि 'हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि जिस तरह से गुलामी, उपनिवेशवाद, चेचक और हैजा इतिहास की बात बन चुके हैं उसी तरह हम (राजग) ग़रीबी को बीते दिनों की बात बना देंगे।' इस चुनावी संकल्प को अमल में लाने के लिए अब 'राजग' सरकार के मुखिया ने ठान ली है। आखिरकार उन्होंने ग़रीबी को "बीते दिनों की बात" बना देने के लिए अन्त्योदय योजना का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले अफसर फाइल-रजिस्टर लेकर ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी की पहचान करेंगे। पहचान हो जाने पर इन्हें 20 किलो अनाज हर महीने दिया जायेगा – गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल तीन रुपया प्रति किलो के हिसाब से। बस देखिये, इसके बाद ग़रीबी कैसे फुर्र हो जाती है!

प्रधानमंत्री जी का काम ऐलान करना है सो, उन्होंने कर दिया है। जो आबादी मेहनत-मजूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकती रहती है, क्या सरकारी अमला उसका पता लगा सकेगी, और जिसका कोई स्थयी ठिकाना ही नहीं उसका राशन कार्ड बनेगा कहां का? योजना आयोग की 'लकड़ावाला कमेटी' ने 1997 में ही इस पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था। दूसरे, इस आबादी के पास न तो राशन कार्ड बनवाने के लिये सामर्थ्य है और न पैसा ही। तीसरे, रोज कमाने और खाने वाली यह आबादी पूरे महीने के लिए अनाज कहां से खरीदेगी और जिसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है वह अनाज रखेगा कहां? अर्थशास्त्री और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' में प्रोफेसर कमलनयन काबरा का कहना है कि अति ग़रीब की न तो ख़रीदने की क्षमता है और न ही उसके पास मासिक आधार पर अनाज रखने की जगह है। यह आप्रवासी नागरिक हैं जो कभी सड़क के किनारे (फुटपाथ पर) अथवा झुग्गी-झोपड़ियों मेंक रहते हैं। अब इस योजना से प्रधानमंत्री जी किसकी ग़रीबी दूर करना चाहते हैं, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

जिस मुल्क में सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग अपनी जगह-जमीन से उजड़ रहे हों, जहां महज आठ वर्षों के दौरान लगभग तीन लाख छोटे-बड़े उद्योगों की बन्दी से चार करोड़ मज़दूर सड़कों पर ढकेले जा चुके हों, जहां फड़-खोखे-गुमटी-ठेला भी लगाना जुर्म हो और जिस समाज में ग़रीब होना ही अपराध हो, क्या वहां ग़रीबी उन्मूलन की बात बेईमानी नहीं है? बाजपेयी जी ग़रीबी उन्मूलन के प्रति चाहे जितनी चिन्ताएं प्रकट कर लें, लेकिन खुद उनकी सरकार द्वारा जो नीतियां बनायी और लागू की जा रही हैं वे ग़रीबों की तबाही बढ़ाने वाली ही हैं। ऊपर की 20 फीसदी आबादी की सुख-समृद्धि के लिये साजो-सामान जुटाये जा रहे हैं, ऐश्वर्य की मीनारें खड़ी हो रही हैं और नीचे की 60 फीसदी आबादी बदहाल और कंगाल हो रही है। समाज में भूख और ग़रीबी के कारण सपरिवार आत्महत्याओं की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

सरकार के ग़रीबी उन्मूलन की हकीकत यह है कि विगत एक दशक में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से "तीव्र आर्थिक विकास" के बावजूद ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती गयी है। आंकड़ों की बाजीगरी के बावजूद सरकार के भाड़े के कलमनवीस और अर्थशास्त्री भी इस तथ्य को छुपा नहीं सकते कि विगत एक दशक के दौरान ग़रीबों की संख्या में 14 करोड़ से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। योजना आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री डा. एस.बी. गुप्ता के अनुसार 1990-91 के मुकाबले 1998 में ग़रीबों की संख्या में 11.5 करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हालात ये हैं कि देश की ऊपर की तीन प्रतिशत आबादी और नीचे की 40 प्रतिशत आबादी की आमदनी के बीच का अन्तर आज 60:1 हो चुका है और यह अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकारी नीतियां ही धनिकों को और धनिक तथा ग़रीबों को और ग़रीब बनाने वाली हैं तो सरकार और उनके देशी-विदेशी पूंजीवादी आकाओं की चिन्ता के क्या कारण हैं?

एक तो भाजपा और उसके राजग के लिए यह लोकरंजक नारा है, ताकि चुनावी जनाधार बचाये रखा जा सके। दूसरे, देशी पूंजीपतियों और विश्व साम्राज्यवादी महाप्रभुओं की चिंता का असल कारण है मंदी। भूमण्डलीकरण के इस दौर में अपनी तमाम कोशिशों और उदारीकृत अर्थव्यवस्था लागू करने के बावजूद विश्व पूंजीवाद महामंदी के दुश्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस दलदल से निकलने की वह जितनी भी कोशिशें कर रहा है, उसमें वह उतने ही गहरे धंसता जा रहा हैं आज हालात ये है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया का बाज़ार तरह-तरह के सामानों से अंटा पड़ा है लेकिन माल बिक नहीं रहे हैं। करोड़पति बनाने से लेकर सोना देने तक और एक सामान खरीदने पर एक मुफ्त तक की तमाम आकर्षक योजनाएं भी मालों की बिक्री बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। कारण, लोगों की क्रय शक्ति में लगातार गिरावट होना है।

ऐसे में पूंजीवादी "विचारकों" का गरीबी को लेकर चिन्तित होना स्वाभाविक है। इसीलिये उनकी सरकारें तरह-तरह के ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की घोषणाएं कर रही हैं, ताकि क्रयशक्ति बढ़े और बाज़र में सामानों की बिक्री बढ़ सके। और यही उनकी सबसे बड़ी विवशता है। पूंजीवादी लूटतंत्र ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़कर ही जीवित रह सकता है, और यह लूटतंत्र भारी आबादी की तबाही को बढ़ाता जाता है और पूंजीवाद मंदी का शिकार होता जाता है। इस प्रकार वह इससे जितना उबरने की कोशिश करता है तो उसमें और उलझता जाता है। और धीरे-धीरे अपने मौत के निकट पहुंच जाता है और वह पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी आप चाहें जितना भी ग़रीबी उन्मूलन कोष बना लें, अन्त्योदय योजना चला लें, आपका निज़ाम इसका उन्मूलन नहीं कर सकता।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
संपादक : डा. दूधनाथ। सम्पादकीय पता : द्वारा ओ.पी. सिन्हा, 69, बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006, सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।